bjpkamaljyoti@gmail.com www.up.bjp.org संवत 2081 युगाब्द 5126 कुल पृष्ठ –32 जुलाई द्वितीय 2024, वर्ष – 34, अंक – 24

वर्तमान
कमल ज्योति

गरीब कल्याण हमारा संकल्प

बजट 2024-25

₹20

प्राकृतिक खेती के विज्ञान
पर
क्षेत्रीय परामर्श कार्यक्रम
19 जुलाई 2024
आयोजक
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार
एवं

वर्तमान
कमल ज्योति

संरक्षक
श्री भूपेन्द्र सिंह
सम्पादक
अरुण कान्त त्रिपाठी
प्रबन्ध/कार्यकारी सम्पादक
राजकुमार
प्रकाशक
प्रो0 श्याम नन्दन सिंह
पृष्ठ संयोजक
ओम प्रकाश पंडित

कार्यालय

कमल ज्योति, 7–विधानसभा मार्ग
लखनऊ – 1
फोन :– 0522–2200187
फैक्स :– 0522–2612437

Email- bjpkamaljyoti@gmail.com

पत्रिका में प्रकाशित आलेखों से सम्पादकीय सहमति अनिवार्य नहीं

मुद्रक
नूतन ऑफसेट मुद्रण केन्द्र, राजेन्द्र नगर, लखनऊ–4

www.up.bjp.org
bjpkamaljyoti
bjpkamaljyoti
@bjpkamaljyoti

गुरू पूर्णिमा
पवित्र सावन मास
कावड़ यात्रा की
हार्दिक बधाई
शुभकामनाऐं!

सम्पादकीय

"सशक्त समृद्ध विकसित भारत बनाने का बजट"

करोना काल के बाद भी भारत निरन्तर आगे बढ़ रहा है। आर्थिक सामाजिक रूप से निरन्तर प्रगति के पथ पर बढ़ रहे भारत को नयी सरकार बनाने के बाद वर्ष 2024–25 का बजट सन्तुलित व लोक कल्याणकारी बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024–24 का केंद्रीय बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ने लगातार 7वीं बार बजट पेश किया. मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट था। पहले से उम्मीद थी कि मोदी 2.0 की सरकार के दौरान जो विज़न तय किए गए हैं, इन्हीं पर इस सरकार की विकास योजनाएं आधारित हैं।

भारत में पिछले तीन दशक में जो विकास देखा गया, वो उपभोग संचालित था लेकिन पिछले वित्तीय वर्ष में इसमें बदलाव देखा गया। इसमें जीडीपी की विकास दर तो 8.2%रही, जबकि उपभोग में सिर्फ 4% की बढ़ोत्तरी हुई। अब ऐसा लग रहा है कि आर्थिक विकास का कारण सकल स्थिर पूंजी निर्माण या निवेश में वृद्धि है, जिसमें करीब 9% की बढ़ोत्तरी देखी गई। मामला चाहे उपभोग संचालित विकास का हो या फिर निवेश योग्य धन का, भारतीय परिवारों की हमेशा इसमें सबसे प्रमुख भूमिका रही है। जीडीपी में निजी उपभोग व्यय की हिस्सेदारी 55% से ज़्यादा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवार, स्थिर पूंजी निर्माण के सबसे बड़े कारक हैं। कुल राष्ट्रीय बचत में इनकी भागीदारी 60% से ज़्यादा है। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर इन परिवारों के हाथ में ज़्यादा पैसा होगा तो ये विकास को बढ़ावा देगा। उच्च सीमांत उपभोग प्रवृत्ति वाला कम आय का परिवार (क्रमिक आय के साथ उपभोग की मांग पर खर्च की जाने वाली वृद्धिशील राशि) उपभोग पर खर्च करेगा, जबकि ज़्यादा आय वाला परिवार बचत करने की उच्च प्रवृत्ति (या उपभोग करने की कम प्रवृत्ति) की वजह से वित्तीय या गैर–वित्तीय बचत के रूप में पैसा बचाएगा। इससे अर्थव्यवस्था में निवेश करने योग्य पूंजी निधि तैयार होगी। ऐसे में उम्मीद थी कि अगर निजी आयकर में कुछ रियायत दी जाती तो इससे परिवारों को फायदा होता। ये विकास में उनके योगदान का पुरस्कार भी होता और इसकी वजह से प्रगति को और रफ़्तार मिलती।

टैक्स में मिली राहत कम आय वाले परिवारों में ज़्यादा दिखेगी क्योंकि मानक कटौती (स्टैंडर्ड डिडक्शन) के स्तर में वृद्धि की गई है। इसके अलावा टैक्स स्लैब में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। इसमें तो कोई शक नहीं कि इनसे विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा लेकिन परिवारों में **"निवेश करने योग्य फंड"** की मांग शायद पूरी नहीं हो पाएगी। ऐसा तभी होता जब 30 प्रतिशत वाला टैक्स स्लैब 15 लाख रुपये की बजाय कम से कम 20–25 लाख रुपये से शुरू होता।

इस बजट में तय की गई निम्नलिखित 9 प्राथमिकताएं। 1–कृषि उत्पादकता और कृषि क्षेत्र में लचीलापन, 2– रोजगार और कौशल, 3– समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, 4– मैन्यूफैक्चरिंग और सर्विसेज, 5– शहरी विकास, 6– ऊर्जा सुरक्षा, 7– बुनियादी ढांचा, 8– इनोवेशन, रिसर्च एंड डिवेलपमेंट और 9– अगली पीढ़ी के सुधार। जो भारत को विश्व की महाशक्ति बनने का मार्ग प्रशस्त करेगा। आज भारत की चुनौतियों का समाधान के साथ नये भारत का निमार्ण करने वाला बजट सबके लिए मंगलकारी होगा।

विकसित भारत का बजट

केंद्रीय बजट 2024-25

नरेन्द्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट लोकहित, गरीब कल्याण के साथ विकसित भारत का बजट है। निरन्तर प्रगतिपथ पर अग्रसर भारत को रखते हुए वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने इस बजट को विकसित भारत का बजट बताया देश विदेश के अर्थशास्त्रीयों ने इस बजट को संतुलित सुखद परिणाम देने वाला बजट बताया हे। वित्त मंत्री बजट रखते हुए अपने उद्बोधन में कहा कि जैसा कि अंतरिम बजट में उल्लेख किया गया है, हमें 4 अलग–अलग जातियों, गरीब, महिला, युवा और किसान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। किसानों के लिए, हमने सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है, जो लागत से कम से कम 50% मार्जिन के वादे को पूरा करता है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ हुआ। भारत की आर्थिक वृद्धि अभी भी शानदार अपवाद बनी हुई है और आने वाले वर्षों में भी ऐसी ही रहेगी। भारत की मुद्रास्फीति कम और स्थिर बनी हुई है तथा 4% के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। मुझे 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए आवंटन 1.52 लाख करोड़ रुपये है। सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम– हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए प्रयास किए हैं। राज्य की पूंजी की आवश्यकता को समझते हुए, हम बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे। चालू वित्त वर्ष में, भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि के साथ 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी। अमृतसर–कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर पर हम बिहार के गया में औद्योगिक विकास को समर्थन देंगे३ यह पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति देगा। हम सड़क संपर्क परियोजनाओं पटना–पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर–भागलपुर राजमार्ग, बोधगया – राजगीर – वैशाली – दरभंगा के विकास में भी सहयोग करेंगे। बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपये की लागत से एक अतिरिक्त दो लेन का पुल बनाया जाएगा। 21,400 करोड़ रुपये की लागत से बिहार के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित करने सहित बिजली परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। बिहार में नए हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाहरी सहायता के लिए बिहार सरकार के अनुरोधों पर शीघ्रता से काम किया जाएगा। हमारी सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना के शीघ्र पूरा होने और वित्तपोषण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है जो आंध्र प्रदेश और उसके किसानों के लिए जीवन रेखा है। सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर

प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी, जिसमें 5000 रुपये प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली मिल सकेगी। यह योजना इसे और बढ़ावा देगी। भारत छोटे रिएक्टरों की स्थापना, भारत छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के अनुसंधान और विकास और परमाणु ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास के लिए सरकार निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगी। सरकार अगले 5 वर्षों में बुनियादी ढांचे के लिए मजबूत राजकोषीय समर्थन बनाए रखने का प्रयास कर रही है। पूंजीगत व्यय 11.11

लाख करोड़ रुपये होगा जो हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% होगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों के अनुकूल सड़कें उपलब्ध कराई जाएंगी३ बिहार में अक्सर बाढ़ आती रहती है। नेपाल में बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं के निर्माण की योजना अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई है। हमारी सरकार 11,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। असम, जो हर साल बाढ़ से जूझता है, को बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता मिलेगी। हिमाचल प्रदेश, जिसे बाढ़ के कारण भारी नुकसान हुआ है, को भी बहुपक्षीय सहायता के माध्यम से पुनर्निर्माण के लिए सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त, उत्तराखंड, जिसे भूस्खलन और बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है, को आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। वित्तीय घाटा 2024–25 तक सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% रहने का अनुमान है। लक्ष्य घाटे को 4.5% से नीचे पहुंचाना है। मैं मोबाइल फोन और मोबाइल च्ब्ठै तथा मोबाइल चार्जर पर ठब्क को घटाकर 15% करने का प्रस्ताव करती हूं। कैंसर के इलाज की तीन दवाओं को मूल सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी।

नई कर व्यवस्था चुनने वालों के लिए, वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये की जाएगी। नई कर व्यवस्था के तहत, कर दर संरचना को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा – 0–रु 3 लाख – शून्य; 3–7 लाख –5%; 7–10 लाख –10%; 10–12 लाख –15%; 12–15 लाख – 20% और 15 लाख से अधिक –30%।

गाँव-गरीब-किसान की समृद्धि का बजट : मोदी

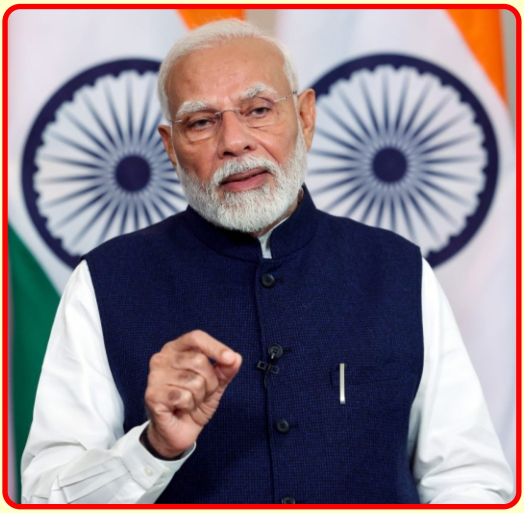

बजट 2024-25

देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने वाले इस महत्वपूर्ण बजट के लिए मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम बहुत–बहुत बधाई की पात्र है। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव–गरीब–किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो नीयो मीडिल क्लास बना है, यह बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। ये नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी। ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है। ये जनजातीय समाज, दलित, पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है। इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस बजट से छोटे व्यापारियों, MSMEs को, यानि की लघु उद्योगों का, उसकी प्रगति का नया रास्ता मिलेगा। बजट में मैन्यूफैक्चरिंग पर भी बल है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बल है। इससे आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी और गति को भी निरंतरता मिलेगी।

रोजगार और स्वरोजगार के अभूतपूर्व अवसर बनाना, ये हमारी सरकार की पहचान रही है। आज का बजट इसे और सुदृढ़ करता है। देश और दुनिया ने PLI स्कीम की सफलता देखी है। अब इस बजट में सरकार ने Employment Linked Incentive scheme की घोषणा की है। इससे देश में करोड़ों–करोड़ों नए रोजगार बनेंगे। इस योजना के तहत, जीवन में पहली नौकरी पाने वाले युवा की पहली तनख्वाह, हमारी सरकार देगी। स्किल डेवलपमेंट और उच्च शिक्षा के लिए मदद हो या फिर 1 करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप की योजना, इससे गांव के, गरीब के मेरे नौजवान साथी, मेरे बेटे–बेटी, देश की टॉप कंपनियों में काम करेंगे, उनके सामने संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। हमें हर शहर, हर गाँव, हर घर entrepreneurs बनाना हैं। इसी उद्देश्य से बिना गारंटी के मुद्रा लोन की लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है। इससे छोटे कारोबारियों, विशेष रूप से महिलाओं, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों में स्वरोजगार को बल मिलेगा।

हम सब लोग मिलकर भारत को ग्लोबल मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाएंगे। देश का MSME सेक्टर, मध्यम वर्ग से जुड़ा हुआ है, एक प्रकार से MSME सेक्टर की ownership मध्यमवर्गीय है और इसी सेक्टर से गरीबों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार भी मिलता है। छोटे उद्योगों को बड़ी ताकत, उस दिशा में हमारा अहम कदम है। इस बजट में MSMEs के लिए Ease of Credit बढ़ाने वाली नई योजना का एलान किया गया है। मैन्युफेक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स इकोसिस्टम को हर जिले तक ले जाने के लिए बजट में अहम घोषणा की गई है। E-Commerce Export Hubs और फूड क्वालिटी टेस्टिंग के लिए 100 यूनिट्स, ऐसे कदमों से वन डिस्ट्रिक्ट

वन प्रोडक्ट अभियान को गति मिलेगी।

ये बजट हमारे स्टार्टअप्स के लिए, इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए ढेर सारे नए अवसर लेकर आया है। स्पेस इकॉनॉमी को बढ़ावा देने के लिए एक हजार करोड़ रुपए का फंड हो, Angel Tax हटाने का फैसला हो, ऐसे कई सारे कदम इस बजट में उठाए गए हैं।

रिकॉर्ड हाई कैपेक्स इकॉनॉमी का एक ड्राइविंग फोर्स बनेगा। 12 नए इंडस्ट्रियल नोड्स देश में नए सैटलाइट टाउन्स का विकास और 14 बड़े शहरों के लिए Transit Plans...bils देश में नए economic hub विकसित होंगे और बहुत बड़ी संख्या में नए रोज़गार बनेंगे।

आज डिफेंस एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड स्तर पर हैं। इस बजट में डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। आज पूरी दुनिया में भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है। और भारत में टूरिज्म के क्षेत्र में नई संभावनाएं बनी हैं। टूरिज्म क्षेत्र, गरीब और मध्यम वर्ग के लिए कई अवसर लेकर आता है। इस बजट में टूरिज्म क्षेत्र पर भी विशेष बल दिया गया है।

NDA सरकार ने पिछले 10 साल में ये सुनिश्चित किया है कि गरीब और मध्यम वर्ग को लगातार टैक्स से राहत मिलती रहे। इस बजट में भी इनकम टैक्स में कटौती और स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि का फैसला लिया गया है। TDS के नियमों को भी सरल किया गया है। इन कदमों से हर टैक्सपेयर को अतिरिक्त बचत होने वाली है। देश के विकास के लिए भारत के पूर्वी क्षेत्र का संपूर्ण विकास–पूर्वोदय के विजन द्वारा हमारे इस अभियान को नई गति, नई ऊर्जा मिलेगी। हम पूर्वी भारत में कई महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाईवेज, वाटर प्रोजेक्ट्स और पावर प्रोजेक्ट्स का निर्माण कर विकास को नई गति देंगे।

इस बजट का एक बहुत बड़ा फोकस देश के किसान हैं। अन्न भंडारण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम के बाद अब हम Vegetable Production Clusters बनाने जा रहे हैं। इससे एक ओर छोटे किसानों को फल–सब्ज़ियों, अन्य उपज के लिए नए बाजार मिलेंगे, बेहतर दाम मिलेंगे–तो दूसरी ओर, हमारे मध्यम वर्ग के लिए फल–सब्जियों की उपलब्धता बढ़ेगी और परिवार के लिए पोषण भी सुनिश्चित होगा। कृषि क्षेत्र में भारत का आत्मनिर्भर बनना समय की मांग है। इसलिए, दलहन, तिलहन की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को मदद की घोषणा की गई है। देश में गरीबी समाप्त हो, गरीब का सशक्तिकरण हो, इस दिशा में भी आज के बजट में प्रमुख घोषणाएं की गई हैं। गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाना तय हुआ है। जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, Saturation Approach के साथ 5 करोड़ आदिवासी परिवारों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ेगा। इसके अलावा ग्राम सड़क योजना, 25 हजार नए ग्रामीण क्षेत्रों को All Weather Roads से जोड़ेगी। इसका लाभ, देश के सभी राज्यों के दूर–दराज गांवों को मिलेगा।

आज का बजट नए अवसर, नई ऊर्जा लेकर आया है। ये ढेर सारे नए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर लेकर आया है। ये Better Growth और Bright Future लेकर आया है। आज का बजट, भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के, उस पूरी प्रक्रिया में कैटेलिस्ट का काम करेगा, विकसित भारत की एक ठोस नींव रखेगा।

सभी देशवासियों को बहुत–बहुत शुभकामनाएं।

विकसित भारत की आधारशिला वाला बजट : नड्डा

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 24–25 विकसित भारत की आधारशिला रखने वाला बजट है। यह सर्व–स्पर्शी और सर्व समावेशी तथा गरीब, महिला, युवा एवं अन्नदाता वर्ग के कल्याण के साथ–साथ उद्योगों एवं इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूती देने वाला दूरदर्शी बजट है। इस बजट में मातृशक्ति के आगे बढ़ने की अमिट छाप है तो कृषि विकास एवं किसानों की खुशहाली का आधार भी। इसमें नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए खुला आसमान है तो गरीबों के चेहरे पर लाने वाली मुस्कान भी। यह बजट आत्मनिर्भर भारत की ऊर्जा से ओतप्रोत और रोजगार सृजन के प्रति समर्पित है।

मैं विकसित भारत की संकल्पना को चरितार्थ करते इस बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी एवं उनकी पूरी टीम को मैं अपनी ओर से एवं पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से बधाई देता हूँ और उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।

पिछले 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी व्यवस्था बनी है जिसमें लाभार्थियों को उनका हक़ बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी लीकेज के सीधे उनके बैंक एकाउंट में पहुँच रहा है। पिछले 10 वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव (PLI) और मेक इन इंडिया पहल से भारत निर्यात में लगातार रिकॉर्ड कायम कर रहा है। पिछले 10 वर्षों में हमारी अर्थव्यस्था, फॉर्मल इकॉनमी की ओर अग्रसर हुई है। डिजिटल इंडिया से देश की अर्थव्यवस्था न केवल मजबूत हुई है बल्कि अब वैश्विक छाप भी छोड़ रही है।

इस बार का बजट 9 प्रमुख प्राथमिकताओं पर आधारित है।

पहला – Productivity & Resilience in Agriculture
दूसरा – Employment & Skilling
तीसरा – Inclusive Human resource development & Social justice
चौथा – Manufacturing & Service
पांचवां – Urban development
छठा – Energy Security
सातवाँ – Infrastructure
आठवाँ – Innovation, Research & Development
नवां – Next Generation Reforms

इस बजट में रोजगार और कौशल विकास तथा नेचुरल फॉर्मिंग को प्रोत्साहित करने वाला है।

प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू करने का निर्णय एक सराहनीय पहल है। इसके 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा, जिससे 5 करोड़ आदिवासी भाइयों को लाभ होगा।

यह बजट गरीब, युवा, महिला और अन्नदाता के प्रति समर्पित बजट है। भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है। मैं पुनः इस कल्याणकारी बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी एवं उनकी पूरी टीम को कोटि–कोटि साधुवाद देता हूँ।

आत्मनिर्भरता का बजट : भूपेन्द्र

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने आम बजट को भारत और भारतवासियों की आत्मनिर्भरता के लिए संकल्पित बजट बताते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उत्कृष्ट नेतृत्व में माननीया केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत 2024–25 का "केंद्रीय आम बजट" भारत को 2047 तक 'विकसित भारत' बनाने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंत्योदय को समर्पित एवं चौतरफा विकास से समावेषित विकसित भारत के लिए बजट निःसंदेह गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा समेत समाज के समस्त वर्गों की उम्मीदों एवं आकांक्षाओं पर खरा उतरने वाला है।

श्री चौधरी ने कहा कि अंत्योदय के प्रण व समग्र विकास के संकल्प को आकार देता यह बजट नए भारत के स्वर्णिम युग को और उत्तम मजबूती प्रदान करेगा। यह बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला है। यह देश के गांव, गरीब, किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला है।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आम बजट गरीब, मध्यम वर्ग, व्यापारियों, उद्यमियों, कर्मचारियों, करदाताओं सहित सभी वर्गों की सहूलियतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस बजट से भारत आर्थिक व सामरिक रूप से सशक्त होगा और देश वैभवशाली व आत्मनिर्भर राष्ट्र निर्माण का संकल्प पूरा करेगा। मैं हर गांव, हर घर को उद्यमी बनाने के लिए संकल्पित इस बजट के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का समस्त देशवासियों और प्रदेशवासियों की तरफ से हृदयतल से हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ।

लोक कल्याणकारी बजट : योगी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में केंद्रीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, विकासोन्मुखी आम बजट 2024–25, 140 करोड़ देशवासियों की आशाओं, आकांक्षाओं और अमृतकाल के सभी संकल्पों को सिद्ध करने वाला है।

आम बजट 2024–25 'विकसित भारत–आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण का आर्थिक दस्तावेज है। इसमें अंत्योदय की पावन भावना, विकास की असीम संभावना और नवोन्मेष की नव–दृष्टि है।

इस बजट में गांव, गरीब, किसान, महिला, नौजवान समेत समाज के सभी तबकों के समग्र विकास का संकल्प, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दृष्टि और वंचित को वंचना से मुक्त कराने का रोडमैप है।

मध्यम वर्ग को बड़ी राहत प्रदान करते हुए प्रत्यक्ष कर प्रणाली के संबंध में नए प्राविधानों की घोषणा स्वागत योग्य है।

'नए भारत' को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी और विश्व का ग्रोथ इंजन बनाने का मार्ग प्रशस्त करते इस लोक–कल्याणकारी बजट के लिए प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार एवं केंद्रीय वित्त मंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन!

भाजपा एक मात्र विचारधारा प्रेरित पार्टी : नड्डा

जनता का हम पर भरोसा, मोदी जी को जनता ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनाः नड्डा

लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश की विस्तृत कार्यसमिति बैठक में मुख्य अतिथि श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को लगातार तीसरी बार चुना है, क्योंकि जनता ने हम पर भरोसा किया है। भाजपा ने 25 जून को –संविधान हत्या दिवस– के रूप में मनाने का फैसला किया तो कांग्रेस परेशान हो गई। हालांकि, यह सर्वविदित तथ्य है कि कांग्रेस ने कई बार संविधान को कमजोर किया है।

कांग्रेस एक परजीवी पार्टी बन गई है, जो अपने दम पर खड़ी नहीं हो सकती, बल्कि दूसरे दलों के वोटों पर निर्भर रहती है, यहां तक कि कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगियों को भी कमजोर कर देती है।

कांग्रेस पार्टी इस समय अपनी जीत का जश्न मना रही है, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी है कि पिछले तीन लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को मिले कुल सीटों की संख्या भी भाजपा को इसबार लोकसभा चुनाव में मिले 240 सीटों से अधिक नहीं है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज रविवार को लखनऊ में भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक को संबोधित किया। इस कार्यक्रम के दौरान मंच पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य और श्री बृजेश पाठक, राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनोद तावड़े, राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री श्री धर्मपाल सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी सहित पार्टी के अन्य नेतागण उपस्थित रहे।

भाजपा ने छद्म धर्मनिरपेक्षता को चुनौती दी है, तुष्टीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास किया है।

श्री नड्डा ने सभी निर्वाचित सांसदों, विधायकों, पार्षदों, जिलाध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों को बधाई देते हुए अपने संबोधन की शुरुआत की। श्री नड्डा ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में सभी सदस्यों ने राष्ट्रीय परिस्थितियों और केंद्र व राज्य द्वारा किए गए कार्यों पर चर्चा करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है।

सदस्यों को दोनों उपमुख्यमंत्रियों और अन्य वरिष्ठ नेताओं का विजन प्राप्त हुआ। श्री नड्डा ने कहा कि 12–13 जून 2016 को लखनऊ में भाजपा राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक हुई थी। उस समय तत्कालीन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि –भाजपा भारत के वर्तमान की पार्टी है और भाजपा भारत के भविष्य की पार्टी होगी।– यह दर्शाता है कि भाजपा वह पार्टी है जो वर्तमान में लगन से काम करती है और उसके पास भविष्य के लिए विजन है। श्री नड्डा ने कहा कि भाजपा सदस्यों और कार्यकर्ताओं के कंधों पर यह जिम्मेदारी है और यह कोई मौसमी जिम्मेदारी नहीं है, यह जिम्मेदारी हमेशा के लिए है।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जहां कुछ पार्टियां उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, पूर्वोत्तर या मध्य भारत जैसे विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित हैं, वहीं भाजपा एकमात्र 'पैन इंडिया पार्टी' है। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण और पूर्वोत्तर हर जगह भाजपा की उपस्थिति है। पार्टी कार्यकर्ताओं को याद रखना चाहिए कि हम 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पार्टी ने कई उतार–चढ़ाव देखे हैं। केवल 2 सीटें होने पर इसका मजाक उड़ाया गया था, लेकिन तब से देश ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व को देखा है और आज पार्टी लगातार तीसरी बार देश पर राज कर रही है। भारत में कुल 1500 पार्टियां हैं, लेकिन किसी में भी आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। ज्यादातर पार्टियां परिवार की राजनीति में लगी हुई हैं और अपने रिश्तेदारों का पक्ष लेती हैं।

भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जो 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मंत्र पर काम करती है। पार्टी का हर नेता और कार्यकर्ता अपने परिवार के कारण नहीं बल्कि अपनी मेहनत और समर्पण के कारण यहां है। श्री नड्डा ने कहा कि हमें अपने साथ आत्मविश्वास और आत्मचिंतन लेकर चलना चाहिए। कोई भी बाहरी व्यक्ति हमें यह नहीं बताएगा कि हमें क्या करना है, हमें स्वयं ही आत्मचिंतन करना होगा।

हम राजनीतिक दल और कार्यकर्ता हैं जिन्हें इस समय यह एहसास होना चाहिए कि हमें इस नेतृत्व को सशक्त करना है, जिसमें मौजूदा परिस्थितियों को बदलने की ताकत है और इसलिए हम कहते हैं कि हम सिर्फ बातचीत को आगे बढ़ाने वाले नहीं हैं, बल्कि उसमें मूल्य जोड़ने वाले हैं। हम सभी कार्यकर्ता हैं और साथ ही नेता भी हैं। नेता और कार्यकर्ता एक ही होते हैं। हर नेता पहले कार्यकर्ता ही होता है।

भाजपा के हर कार्यकर्ता में चुनौतियों को स्वीकार करने और इस सोच के साथ आगे बढ़ने की ताकत है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस समय अपनी जीत का जश्न मना रही है, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी है कि पिछले तीन लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को मिले कुल सीटों की संख्या भी भाजपा को इसबार लोकसभा चुनाव में मिले 240 सीटों से अधिक नहीं है। कांग्रेस पार्टी पिछले तीन लोकसभा चुनावों में 100 सीटें भी नहीं जीत पाई है। अगर विपक्षी गठबंधन में शामिल सभी दलों की सीटों को मिला दें, तो भी वे भाजपा की संख्या से मेल नहीं खा सकते। 13 राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने एक भी सीट नहीं जीती। गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 64 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था। उनमें से कांग्रेस को केवल 2 सीटें मिलीं, जबकि भाजपा को 62 सीटें मिलीं।

उनका स्ट्राइक रेट 26% है, जबकि अन्य दलों के साथ गठबंधन में उनका स्ट्राइक रेट 50% है। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी बन गई है, जो अपने दम पर खड़ी नहीं हो सकती, बल्कि दूसरे दलों के वोटों पर निर्भर रहती है, यहां तक कि कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगियों को भी कमजोर कर देती है। कांग्रेस पार्टी आज बैसाखियों के सहारे खड़ी है। श्री नड्डा ने कहा कि संविधान के खतरे में होने की भ्रांति लोगों में फैलाई गई है, लेकिन संविधान को कमजोर करने का इतिहास कांग्रेस पार्टी का ही है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी ने अपने खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने -प्रदर्शन, सुधार और परिवर्तन- की नीति को प्रोत्साहित किया है और उसी नीति को सीएम श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में लागू किया गया।

का फैसला आने के बाद देश में आपातकाल लगाया था, उस वक्त लोकतंत्र और संविधान की हत्या की गई और आज वही पार्टी संविधान की रक्षक बनने का ढोंग कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 90 बार लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों को गिराया है। वहीं दूसरी ओर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा ने 10 वर्षों में केवल जम्मू–कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू किया और वह भी इस आश्वासन के साथ कि यह अस्थायी है और वहां चुनाव होंगे।

कांग्रेस वर्ग विशेष के लिए धर्म आधारित आरक्षण का प्रावधान करती है, लेकिन संविधान में लिखा है कि धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं होगा। इसके बावजूद आंध्र प्रदेश में चार बार धर्म के आधार पर आरक्षण लागू करने का प्रयास किया गया। कर्नाटक में भाजपा धर्म के आधार पर आरक्षण खत्म करती है, लेकिन कांग्रेस सत्ता में आती है, तो धर्म के आधार पर आरक्षण फिर से लागू करने का प्रयास करती है। ये कृत्य संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। जब भाजपा ने 25 जून को –संविधान हत्या दिवस– के रूप में मनाने का फैसला किया तो कांग्रेस परेशान हो गई। हालांकि, यह सर्वविदित तथ्य है कि कांग्रेस ने कई बार संविधान को कमजोर किया है।

भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है, जो देश को आगे ले जाने में सक्षम है और यह संदेश हमारे मन में स्पष्ट रूप से गूंजना चाहिए। भाजपा गर्व के साथ कह सकती है कि जब डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अनुच्छेद 370 को हटाने का आह्वान किया था, तो हम जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं ने, चार पीढ़ियों तक अपना जीवन समर्पित कर दिया था और तब जाकर 5 अगस्त 2019 का वह ऐतिहासिक दिन आया जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दृढ़ संकल्प और गृह मंत्री श्री अमित शाह की रणनीति के माध्यम से अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया। भाजपा ने हमेशा कहा है कि राम मंदिर हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है। 1987–88 के पालमपुर संकल्प में भाजपा ने कहा था कि वह राम मंदिर निर्माण के मार्ग को आगे बढ़ाने में सक्रिय योगदान देगी और इस कथन के लिए हमें अनेक जीत और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन 22 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की।

भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके पास सबसे ज़्यादा जनसमर्थन है। एनडीए की 17 राज्यों में सरकार है, जबकि भाजपा सिर्फ़ 13 राज्यों में सत्ता में है। देश का 58% से अधिक क्षेत्र भाजपा के शासन में है, और देश की 57% से अधिक जनसंख्या पर भाजपा का शासन है।

भाजपा एकमात्र विचारधारा आधारित पार्टी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने हमें "एकात्म मानववाद" का मंत्र दिया था। उस समय लोग कहते थे कि हम एकात्म मानववाद को नहीं समझते। 1977 में जब जनता पार्टी की केंद्र और राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में सरकार बनी तो हमने "अंत्योदय" के माध्यम से इस मंत्र को लागू करना शुरू किया। उन्होंने ने कहा कि भाजपा एकमात्र कैडर आधारित पार्टी है, जहां हर कोई जिम्मेदारी की भावना के साथ आया है।

भाजपा 18 करोड़ सदस्यों वाली पार्टी है और इसके 1 लाख 16 हजार शक्ति केंद्र हैं। पार्टी के 6 लाख 80 हजार बूथ अध्यक्ष और 10 लाख 40 हजार से अधिक बूथों पर समितियां भी हैं। भाजपा के पास सबसे ज़्यादा सांसद, 1500 से ज़्यादा विधायक, 300 से ज़्यादा एमएलसी, 200 से ज़्यादा मेयर और हज़ारों ब्लॉक सदस्य हैं।

भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके पास सबसे ज़्यादा जनसमर्थन है। एनडीए की 17 राज्यों में सरकार है, जबकि भाजपा सिर्फ़ 13 राज्यों में सत्ता में है। देश का 58% से अधिक क्षेत्र भाजपा के शासन में है, और देश की 57% से अधिक जनसंख्या पर भाजपा का शासन है।

श्री नड्डा कहा कि भाजपा ने छद्म धर्म निरपेक्षता को चुनौती दी है, तुष्टीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास किया है। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ताओं से ज्यादा सामाजिक कार्यकर्ता हैं। भाजपा जितना सामाजिक कार्य किसी भी अन्य राजनीतिक दल ने नहीं किया है। 2014 से पहले भारत भ्रष्टाचार, नीतिगत पक्षाघात और डगमगाती अर्थव्यवस्था के लिए बदनाम था। उत्तर प्रदेश भी माफिया राज, तुष्टीकरण की राजनीति, महिलाओं के उत्पीड़न और राज्य से लोगों व व्यापारियों के पलायन से त्रस्त था। राजनीति गतिशील है और हमेशा सापेक्ष होती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने प्रदर्शन, सुधार और परिवर्तन– की नीति को प्रोत्साहित किया है और उसी नीति को मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने भी देश भर में 'स्पीड, स्केल और स्किल' को लागू किया है।

माननीय श्री नड्डा ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में भाई–बहन हैं और दोनों ही पढ़े–लिखे अनपढ़ हैं, जब वे बेरोजगारी और महंगाई की बात करते हैं, तो उन्हें पता ही नहीं होता कि वे क्या कह रहे हैं? आज कोविड–19 और यूक्रेन–रूस संघर्ष के प्रभाव के बावजूद आईएमएफ का कहना है कि भारत अर्थव्यवस्था में अग्रणी देशों में शामिल है। मॉर्गन स्टेनली का भी कहना है कि 2014 के बाद का भारत अलग है। मूडीज की रिपोर्ट में भी आने वाले दिनों में भारत की विकास दर 6% से अधिक रहने का अनुमान लगाया गया है।

अमेरिका की विकास दर 2.7%, जर्मनी की 0.2%, फ्रांस की 0.7%, जापान की 0.9% और यूके की 0.5% है जबकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विकास दर 6.8% है। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि रोजगार नहीं है, लेकिन वे यह नहीं समझते कि जब अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ता है, तो रोजगार के अवसर अपने आप बढ़ जाते हैं। रेलवे, पुल, हवाई अड्डे, राजमार्ग आदि के विकास से रोजगार के अनगिनत अवसर पैदा होते हैं। चाहे शिक्षित हों या अशिक्षित, लोगों को यह एहसास होना चाहिए कि देश बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा, इसकी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता।

भारत दुनिया में स्टील उत्पादन में दूसरे नंबर पर है। भारत पेट्रोकेमिकल और फार्मास्युटिकल में भी आगे बढ़ चुका है। आज सबसे सस्ती और सबसे कारगर दवाई आज भारत बना रहा है। आज भारत में 97% मोबाईल बन रहे हैं। भारत जापान को पीछे करके दुनिया कि तीसरा सबसे बड़ा आटोमोबाईल मार्केट बन गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश को दी जाने वाली करों के हस्तांतरण मे साढ़े तीन गुना बढ़ोत्तरी करी है। पहले केंद्र सरकार से उत्तर प्रदेश को 1.2 लाख करोड़ रुपए का फंड मिलता था, आज 4.4 लाख करोड़ रुपए विकास के लिए मिल रहा है। आयुष्मान भारत योजना में उत्तर प्रदेश ने अच्छा प्रदर्शन किया है और उत्तर प्रदेश में 27 नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं। एथनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम स्थान पर है, 118 करोड़ लीटर एथनॉल का उत्पादन आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है। 1 करोड़ महिलाओं को लगभग 12 हजार रुपये सालाना की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। सुमंगला योजना के तहत 14 लाख महिलाओं को लाभ मिल रहा है।

माननीय श्री नड्डा ने कहा कि एक तरफ उत्तर प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है और नहीं दूसरी तरफ कॉंग्रेस शासित कर्नाटक में राज्य सरकार के वित्त सचिव ने खुद कहा कि कर्नाटक मे विकास के लिए कोई पैसा नहीं रह गया है। श्री नड्डा ने कहा कि कमल खिलने से सुशासन आता है और विपक्षी सरकारों मे व्यापारी पलायन करते हैं, बहू–बेटियाँ सुरक्षित नहीं रहती हैं और घोटाले पर घोटाले होते हैं। 2019 मे चुनाव के रिजल्ट आने से पहले ही अराजकता शुरू हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी की फौज विपक्षी दलों को हमेशा के लिए आगे आने से रोक सकती है।

भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ आगे बढ़कर पार्टी को सुदृढ़ बनाते हुए और पार्टी को पूरी ताकत से आगे बढाएंगे। उड़ीसा में भाजपा को 46% वोट मिला है और अरुणाचल प्रदेश में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बन गई है। आंध्र प्रदेश मे एनडीए की सरकार आ गई है। तमिलनाडु मे भाजपा को 11% से ज्यादा वोट भाजपा को मिले हैं। केरल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हजारों की संख्या मे अपना जीवन दांव पर लगाकर लड़ाई लड़ी है, और पहली बार केरल मे भी भाजपा का लोकसभा में प्रतिनिधित्व हो रहा है और भाजपा की वोट संख्या 3% से बढ़कर 6% और 6% से बढ़कर 19.7% हो गया है। भाजपा का कमल पूरे देश में खिल रहा है और उसका केन्द्रबिन्दु उत्तर प्रदेश है, जहां भाजपा सरकार की गंगोत्री काशी है, वहां भी कमल खिला है और हमेशा खिलता रहेगा, इसी विश्वास के साथ भाजपा निरंतर कार्य करते हुए आगे बढ़ती रहेगी।

कार्यकर्ता का सम्मान हमारी प्राथमिकता : भूपेन्द्र

भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनपुरी में गोमती नदी के तट पर माननीय मुख्यमंत्री जी सहित इस सभागार में उपस्थित सभी अतिथियों और कार्यकर्ता बन्धुओं का मैं स्वागत एंव अभिनंदन करता हूं। मैं आज इस अवसर पर याद करना चाहता हूं इस शहर के वास्तविक भारतीय वास्तुविद लखना पासी को जिनको याद किये बिना यह प्रदेश कार्यसमिति अधूरी रहेगी। देश का मन उत्तर प्रदेश है। भारत की आत्मा अयोध्या, काशी और मथुरा में बसती है जो हमारी पहचान है। इस ऐतिहासिक और गौरवशाली परम्परा के संवाहक उत्तर प्रदेश की धरती से आमजन के सपनों को साकार करने के लिए देश की अहर्निश सेवा में लगे हम सभी के मार्गदर्शक श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार काशी से सांसद बनाकर राष्ट्र सेवा के लिए प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित करने का महान सौभाग्य सभी कार्यकर्ताओं को मिला है। केंद्र में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर माननीय मोदी जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी एवं केंद्रीय नेतृत्व को हार्दिक शुभकामनायें एवं आप सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूँ।

हम सभी जनवरी 2024 में संपन्न हुई प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में मिले थे। आज लोकसभा चुनाव 2024 के संपन्न होने के उपरांत एक बार फिर हम सभी यहां पर मिल रहे हैं। यह प्रदेश कार्यसमिति बृहद रूप से आयोजित की गई है जिसमें हम सभी को कार्यसमिति समापन सत्र में भाजपा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन मिलेगा, जो हमारे लिये अत्यंत प्रसन्नता का विषय है।

अध्यक्षीय उद्बोधन

उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है। यहां पर सबसे उर्वरा भूमि है। यह देश की आत्मा व हृदय स्थल है। भगवान राम और कृष्ण ने यहीं जन्म लिया। यहीं पर बाबा विश्वनाथ घाम है। वैदिक ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाली भूमि नैमिषारण्य है। शक्तिपीठों से जुड़ी परंपरा भी यहां पर है। पूर्व में विपक्ष के जो लोग इस सामर्थ्य को नहीं समझते थे वे कांवड़ यात्रा पर रोक लगाते थे। लेकिन, आज 500 वर्षों के बाद अयोध्या में श्रीराम मंदिर का निर्माण हमारी विरासत का सम्मान है। सही अर्थों में कहा जाये तो हम सभी भाजपा कार्यकर्ता परंपराओं को अपनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं।

क्योंकि, भाजपा ही एक मात्र राजनीतिक संगठन है जिसके कार्यकर्ताओं के मन में पहले देश, फिर दल और सबसे अंत में स्वयं के हित की भावना आती है। हमारा यह प्रदेश उसी दृष्टिकोण के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मागदर्शन में वैभवशाली भारत, शक्तिशाली भारत, आत्मनिर्भर भारत के रूप में आकार ले रहा है। आज हमें गर्व हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार केन्द्र में भाजपा की सरकार बनी है जिसका हम सभी आज हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास से संभव हो सक है। जिसके लिये आप धन्यवाद के पात्र हैं।

सपा और कांग्रेस जैसे परिवारवादी और जातीयवादी शक्तियों ने अफवाह एवं भ्रम फैलाकर प्रदेश की जनता को जातीय अखाड़ों में बदलने की कोशिश की। मुस्लि मतदाताओं का भयादोहन करके उनका वोट लेने का कांग्रेस और सपा ने नया तरी तलाशा और उनको अपने एजेंडे का शिकार बनाया जिसमें उन्हें आंशिक सफलता मिली। इसीलिए हमारे समक्ष यह चुनौती है कि अभी से भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता जनता के बीच घर–घर जाकर युद्धस्तर पर इस झूठ और अफवाह का पर्दाफाश का है और इनके विभाजनकारी मंसूबों पर पानी फेरना है। सर्वसमाज को लेकर ह निरंतर आगे जाना है। जो भूले भटके हैं उनको गले लगाना है। फिर से लोगों के जाना है और सबको साथ लेकर समाज और राष्ट्र को विकास के पथ पर लेकन बढ़ना है।

अगर हम आंकडों पर बात करें तो सपा और कांग्रेस ने मिलकर 2024 के चुनावों में 43.05 फीसदी वोट प्राप्त किया है। जबकि भाजपा ने अकेले 41.37 फीसदी वोट प्राप्त किया है। अगर भाजपा में हम अपने सहयोगी दलों का वोट जोड़ दें तो सपा–कांग्रेस हमसे आज भी पीछे है। केवल संविधान खतरे में है खटाखट 8500 रू0 का झूठा भ्रमजाल फैलाकर सपा और कांग्रेस ने बहुजन वोट के सहारे 1.68 फीसदी वोट अधिक हासिल किया है।

अखिलेश यादव जी, आपको सावधान कर रहा हूं यह कांग्रेस भष्मासुर है और बहुत जल्दी आपको ठिकाने लगा देगी। कांग्रेस की नजर आपके मुस्लिम वोट पर पड़ गई है। कांग्रेस की सोच एवं उनकी कार्यशैली में लोकतंत्र की कोई गुंजाइश ही नहीं है। कांग्रेस का एक इकोसिस्टम है जो हारने वालों को जीता हुआ बताकर जीतने वालों पर प्रश्न खड़े करता है। 13 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सीटें शून्य हैं। कांग्रेस पार्टी जहां भी जीती है वहां अपने वोटों से नहीं जीती, बल्कि दूसरी पार्टियों के वोटों पर जीती है।

आपातकाल की जनक कांग्रेस जब भी सत्ता में रही उस समय जिसने विरोध किया, उसे समाप्त करने में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। देश में सबसे ज्यादा बार धारा

1951 में हमने जो संकल्प लिये थे, आज पूरे हो रहे हैं। आजादी के बाद भाजपा पहला राजनीतिक दल है, जिसने बलिदान दिया। डॉ श्याम प्रसाद मुखर्जी का कश्मीर में संदिग्ध परिस्थितियों में निधन हुआ। एक देश में दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे को साकार करते हुये प्रधानमंत्री जी ने धारा 370 को हटाया। जिससे आज जम्मू और कश्मीर लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ रहा है। हमने अयोध्या में राममंदिर बनाने का सपना देखा, वह सपना प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से साकार हो गया है। हमारी सरकार बहुसंख्यकों की आस्था का सम्मान और अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नई ऊंचाई को छू रही है। राष्ट्रीय विचार की राजनीति हमारी प्रतिबद्धता है साथ ही 'सेवा ही संगठन' की अवधारणा को लेकर किए गए कार्यों से भाजपा का मानवीय स्वरूप जनता तक पहुंचा है। सेवा ही संगठन का मूल मंत्र है इसी ध्येय के साथ पार्टी सफलता के कीर्तमान स्थापित कर रही है।

2014, 2017, 2019, 2022 के विधानसभा चुनाव और फिर नगर निकाय चुनाव में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शानदार नतीजे हासिल किए और हमने प्रचंड विजय प्राप्त की। 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहा लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने परिश्रम की पराकास्ठा दिखाते हुए अपना पूरा सहयोग दिया। जिसके कारण हमारा सौभाग्य है कि, लगातार तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनी है। ऐसा स्वतंत्र भारत की राजनीति में 6 दशक के बाद संभव हो पाया है। यह सभी भाजपा

356 का प्रयोग करके सरकारों को गिराने का काम कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। पिछले तीन चुनावों से कांग्रेस ने प्रदेश में अलग–अलग दलों के साथ जाने का प्रयास किया और अपना स्वार्थ ठीक हो जाने के बाद उस पार्टी को रसातल में पहुंचा दिया। इसलिये आज दलित वंचितों की पार्टी के वोट झूठ बोलकर इन दलों ने भले ही ले लिया हो लेकिन इनके द्वारा कभी भी दलितों शोषितों के भले के लिये काम नहीं किया गया है। 25 जून आपातकाल के दिवस को "संविधान हत्या दिवस" घोषित करने के लिए यह कार्यसमिति माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का अभिनन्दन करती है। भारतीय जनता पार्टी एक मात्र पार्टी है जो अपनी विचारधारा पर अडिग है। कांग्रेस पार्टी का तो कोई वैचारिक आधार है ही नहीं। कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब अंबेडकर का विरोध किया है। उनको कांग्रेस ने कभी अपने संगठन का चुनाव नहीं लड़ने दिया। बाबा साहब अंबेडकर को कैबिनेट का सदस्य होने के बाद भी इस्तीफा देना पड़ा था। कांग्रेस ने सदैव बाबा साहब का अपमान जीते–जी तो किया ही और मरणोपरान्त भी उनका सम्मान नहीं दिया।

हमारी सरकारों ने बाबा साहब से सम्बन्धित स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया है। बाबा साहब के सम्मान में हमारी सरकार द्वारा 26 नवम्बर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की परम्परा शुरू की गई है जो कांग्रेस अपने सत्ता के 50 वर्षों में नहीं कर पाई। बाबा साहब को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी गैर कांग्रेस पार्टी द्वारा दिया गया।

लोहिया को अपना आदर्श मानने वाली समाजवादी पार्टी शुद्ध रूप से परिवारवादी पार्टी में परिवर्तित हो गयी है। इनकी परिवारवादी मानसिकता, वैभवशाली रहन–सहन, अपराध केन्द्रित राजनीति को संरक्षण इत्यादि कृत्यों को देखकर स्वर्ग में लोहिया जी की आत्मा भी विलाप कर रही होगी। कांग्रेस पार्टी की सोच में विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं है। अगर कोई विरोध करता है तो कांग्रेस उसे खत्म कर देती है। कांग्रेस के नेता संविधान की प्रति जरूर लेकर घूमते हैं, लेकिन उन्होंने कभी इतिहास नहीं पढ़ा है। संविधान में सबसे अधिक बार संशोधन करने वाली और चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारों को सबसे अधिक बार धारा–356 लगाकर बर्खाशत करने वाली कांग्रेस से संविधान को आज सबसे ज्यादा खतरा है।

जबकि हमारा मंत्र सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास है। हमारी केन्द्र और राज्य की सरकारें सभी के लिये एक समान कार्य करने में विश्वास करती है। प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना तक हमारा सिद्धांत सभी के लिये एक है। प्रदेश के अंदर माननीय योगी जी के नेतृत्व में हमने जाति धर्म, संप्रदाय वर्ग से उपर उठकर पारदर्शी तरीके से प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश की जनता को दिया। हिन्दू हो या मुस्लिम हमारी सरकारों में सभी को प्रत्येक योजना का लाभ मिलता है।

हम सभी जानते हैं कि, भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबी यात्रा तय की है। दो सांसदों से लेकर आज देश में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है। हमारा आधार पार्टी का सिद्धांत, कार्यकर्ताओं का परिश्रम और भाजपा की सरकारों के लोक कल्याण के काम हैं। भाजपा गरीब कल्याण के आधार पर आगे बढ़ने वाली पार्टी है। प्रदेश में जब हमारे विरोधी दलों की सरकार थी तो वो लोग कट, कमीशन और करप्शन में लिप्त थे। वे रात–दिन अपने परिवार और रिश्तेदार की चिंता में लगे रहते है वहीं दूसरी तरफ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा पूरे देश को अपना परिवार मानती है।

आज आप सभी को इस कार्यसमिति के माध्यम से मैं अपने इस परिवार को सजग करना चाहता हूं कि, यह समय चिन्ता करने का नहीं है। यह समय है चिन्तन करने का। चिन्तन को कार्यशैली में बदलने और दलित वंचित शोषित समाज के बीच जाकर उसका भ्रम दूर करने का समय है।

हमने समाज के लिये किया है। समाज के लिये जिया है। समाज से लिया है इसलिये समाज को अभी बहुत कुछ देना भी है। पंडित जी ने एक बार संगठन की महत्ता पर बल देते हुए कहा था कि "हमें इस प्रकार कार्य करना है कि आज का विरोधी कल हमारा मतदाता बने। कल का मतदाता परसों हमारा सदस्य और परसों का सदस्य हमारा सक्रिय कार्यकर्ता बनें।"

केन्द्र में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण, विश्व महाशक्ति के रूप में भारत की प्रभावी छवि, देश के बाह्य और आंतरिक दुश्मनों को मुहतोड़ जवाब, भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के प्रति तीव्र गति से अग्रसर जैसे चतुर्दिक क्षेत्रों में पिछले 10 वर्ष का कार्यकाल इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जायेगा। वहीं प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मजबूत कानून व्यवस्था की बात हो चाहें पूरे प्रदेश में सड़कों और एक्सप्रेसवे का जाल बिछाने की बात हो, शासकीय स्कूलों की कायाकल्प की बात हो, सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज या साढ़े छह लाख युवाओं को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त नौकरियों देने की बात हो हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश को सबसे तेजी के साथ विकसित प्रदेशों की सूची में लाकर खड़ा कर दिया है। हमें विकसित भारत 2047 के संकल्प को सिद्ध करते हुए भारत को दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पॉवर बनाना है।

कार्यकर्ता का सम्मान हमारी प्राथमिकता है जिसके साथ को भी समझौता नहीं किया जाएगा। पार्टी अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।

भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, यहाँ तो मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को संगठन में कार्य करते–करते पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। मै प्रधानमंत्री जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एवं शीर्ष नेतृत्व का आभारी हूँ जिन्होंने भरोसा जताते हुये अध्यक्ष के रूप में मुझे आप लोगों के साथ काम करने का अवसर दिया। 62 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी पार्टी को लगातार तीसरी बार केन्द्र में सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमारे करिश्माई नेता माननीय नरेन्द्र मोदी जी और कार्यकताओं के परिश्रम के बदौलत ही ऐसा सम्भव हो पाया है। विपक्ष के सारे दल मिलकर इतनी सीट भी प्राप्त नहीं कर सके जितनी भाजपा ने अकेले प्राप्त की है। कांग्रेस लगातार तीसरी बार 100 सीटें भी नहीं प्राप्त कर सकी है। हम चुनौतियों से निकल कर और मजबूत होने वाले लोग है। हमारे मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बैन लगाया गया, देश पर आपातकाल थोपा गया, नब्बे के दशक में आतंकवाद, नक्सलवाद, जातिवादी शक्तियों के उभार, बंगाल केरल तथा कई राज्यों में विचारधारा के आधार पर हमारे कार्यकर्ताओं पर प्राण घातक हमलें, हमने सभी चुनौतियों को मुहतोड़ जवाब दिया और चन्दन की तरह शीतल रहते हुए, कुन्दन की तरह तप कर के निकले है और इन समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी ताकतों को परास्त करते हुए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित है। भाजपा संख्या बल में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के साथ बूथ से लेकर प्रदेश तक संगठन के ताकत के आधार पर सबसे मजबूत पार्टी है। विपक्षियों के झूठ, अफवाह एवं तुष्टीकरण का जवाब हम बूथ के कार्यकर्ताओं की ताकत और अपने मूलमंत्र प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय और लक्ष्य अंत्योदय के माध्यम से देने के लिए कृतसंकल्पित है। हम सभी कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर घर–घर प्रत्येक मतदाता तक जाएँगें अपनी सरकार के अंत्योदयी योजनाओं का प्रचार करेंगे और विपक्ष के झूठ और अफवाह का पर्दाफाश करेंगे।

मैं अध्यक्ष के रूप में आपको आश्वस्त करता हूँ कि कार्यकर्ता का सम्मान हमारी प्राथमिकता है जिसके साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। पार्टी अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। आइये हम सब मिलकर संकल्प ले कि आगामी 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों में शतप्रतिशत विजय श्री हासिल करेंगे। अगली लड़ाई स्वार्थी परिवारवादियों और मोदी के परिवार के बीच है, राष्ट्र विरोधियों और राष्ट्रभक्तों के बीच में है, धर्म और अधर्म के बीच में है, तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण के बीच में है, भ्रष्टाचारियों और सदाचारियों के बीच में है। 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का मोदी जी का संकल्प को हम सभी कार्यकर्ता पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। अभी से हम सभी कार्यकर्ताओं को कमर कस कर प्राण–पण से लग जाना है और 2027 के चुनाव में विरोधियों को मात देते हुए भाजपा की प्रचन्ड विजय को सुनिश्चित करना है। अब मैं भारत रत्न श्रद्धेय अटल जी की कविता के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं–

चिंतन चरित्र में अब, विकृति बढ़ी है।
चहुंओर कौरवों की सेना खड़ी है।।
फिर से जितनी बाधाएं आती है आएं।
चाहें फिर से घिरें प्रलय की घोर घटाएं।।
हमको आग लगाकर जलना होगा।
फिर से कदम मिलाकर चलना होगा।।

2027 में फिर से प्रदेश में फहरेगा भाजपा का परचम : योगी आदित्यनाथ

भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की प्रदेश कार्यसमिति बैठक में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में 10 सीटों पर होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी को अभी से सक्रिय होना होगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा सांसद के साथ ही विधायकगण, एमएलसी, जिला पंचायत अध्यक्ष, महापौर, ब्लॉक प्रमुख, चेयरमैन और पार्षद सभी लोग आज से ही 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं। हमें एक बार फिर प्रदेश में भाजपा का परचम लहराना है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया पर सुपर एक्टिव होना होगा और किसी भी प्रकार की अफवाहों का तत्काल खंडन करना होगा। मुख्यमंत्री योगी रविवार को डॉ राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के डॉ भीमराव अंबेडकर सभागार में आयोजित प्रदेश कार्यसमिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमने यूपी में 2014, 2017, 2019 और 2022 में बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए विपक्ष पर लगातार दबाव बनाए रखा था। 2014 और उसके बाद के चुनावों में जितना मत प्रतिशत भाजपा के पक्ष में था, 2024 में भी भाजपा उतना वोट पाने में सफल रही है, लेकिन वोटों की शिफ्टिंग और अति आत्मविश्वास ने हमारी अपेक्षाओं को चोट पहुंचाई है। जो विपक्ष पहले हार मान के बैठ गया था, वो आज फिर से उछल–कूद मचा रहा है। 'किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं' है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2022 में विपक्ष चुनाव के बाद मारपीट पर उतारू हो गया था। तब हमारे सभी कार्यकर्ताओं को ये लगा कि वास्तव में हमारी सरकार का माफिया मुक्त यूपी का विहान इन्हीं गुंडों के लिए है। आज आपके सहयोग से हमें यूपी को माफिया मुक्त करने में सफलता मिली है। इसके अलावा अयोध्या में श्रीरामलला अपने मंदिर में विराजमान हुए तो 500 वर्षों का इंतजार भी समाप्त हुआ है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने कार्य किया है। जब आप विपक्ष में थे तब जनता के मुद्दों को लेकर लड़ते थे, जब सरकार में हैं तो यूपी में सुरक्षा का वातावरण देखने को मिल रहा है।

कभी मोहर्रम में सड़कें सूनी हो जाती थीं। आज मोहर्रम हो रहा है ये पता भी नहीं चलता। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे। आज कहा जाता है कि गरीब की झोपड़ी नहीं तोड़ेंगे, तार नहीं तोड़ेंगे। हमारा स्पष्ट तौर पर निर्देश है कि पर्व और त्योहार मनाना है तो नियमों के अंतर्गत मनाओ, वरना घर में बैठ जाओ। भाजपा ने पूरे देश में विधि और सुशासन की सरकार को चलाके दिखाया है। मुख्यमंत्री ने कोरोना काल की चर्चा करते हुए कहा कि तब प्रधानमंत्री मोदी ने सेवा ही संगठन का मंत्र दिया था। उस वक्त भी भाजपा और आरएसएस के

कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर जनता की सेवा कर रहे थे, मगर अन्य कोई राजनीतिक दल तब नहीं दिखा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जाति, मत, मजहब के नाम पर भेदभाव नहीं करते। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन किसी की जाति, धर्म देखकर नहीं मिल रहा। कोरोना काल में भी भूख से मौत और आत्महत्या नहीं होने दिया गया। उस कालखंड में भी हमारे कार्यकर्ता अपनी जान की परवाह किये बगैर लगातार कार्य करते रहे। जिस कोरोना के सामने दुनिया की बड़ी–बड़ी ताकतें नतमस्तक हो गई, उसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में समाप्त करने का कार्य हम सबने मिलकर किया। मुख्यमंत्री योगी ने इन्सेफेलाइटिस का मामला सामने रखते हुए कहा कि जब श्री जेपी नड्डा जी देश के स्वास्थ्य मंत्री बने थे तब मैं एक सांसद के नाते उनसे मिला था। इन्सेफेलाइटिस को हमारी सरकार ने प्राथमिकता पर रखा और 40 साल से ज्यादा समय से पूर्वांचल में आतंक मचाने वाली इस बीमारी को हमने जड़ से समाप्त कर दिया।

गोरखपुर में एम्स शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि यूपी में कभी इन्फ्रास्ट्रक्चर कल्पना थी, आज कहीं जाइए आपको फोरलेन कनेक्टिविटी मिलेगी। 'समाजवादियों ने राम, कृष्ण और शिव की परंपरा को लहुलुहान किया' मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हमने बुंदेलखंड को डकैत मुक्त बनाने का संकल्प लिया था जो कि पूरा हो चुका है। प्रदेश माफिया मुक्त हो चुका है। उन्होंने डॉ लोहिया को याद करते हुए कहा कि लोहिया जी ने कहा था कि जबतक भारत में राम, कृष्ण और शिव की पूजा होगी भारत को कोई समाप्त नहीं कर सकता। मगर इन समाजवादियों ने राम, कृष्ण और शिव की परंपरा को लहुलुहान किया था।

मुख्यमंत्री श्री योगी ने कहा कि जब प्रयागराज में राजू पाल और उमेश पाल की हत्या होती है, तब क्या ये लोग पिछड़ी जाति के नहीं थे। कृष्णानंद राय के साथ रमेश पटेल और रमेश यादव भी मौत के घाट उतार दिये गये, क्या ये पिछड़ी जातियों के नहीं थे। आज माफिया के लिए फातिहा पढ़ने वाले फिर से चिल्ला–चिल्ला कर चुनौती देने की स्थिति में आ गये हैं।

कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नाम डॉ भीमराव अंबेडकर के नाम पर था। सपा के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उसका नाम बदल दिया। हमारी सरकार आने के बाद हमने फिर से बाबा साहब के नाम पर विश्वविद्यालय का नामकरण किया। समाजवादी पार्टी हमेशा से दलित चिंतकों और महापुरुषों का अपमान करती रही है। इन लोगों ने अनुसूचित जाति के आरक्षण में सेंध लगाने का कार्य किया। एससी के स्कॉलरशिप को रोकने का काम किया। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाबा

सपा, कांग्रेस, साँप नाथ, नाग नाथ : मौर्य

भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि लोकसभा चुनाव में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सरकार बनी है। पहली बार उड़ीसा में जय जगन्नाथ हुआ है। सिक्किम में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है, आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी है। इसके लिए कार्यकर्ताओं का धन्यवाद, आभार और अभिनंदन है। उन्होंने कहा कि जो योगदान हम कार्यकर्ताओं ने 2014 में मोदी जी की सरकार बनाकर दिया। वर्ष 2017 में प्रदेश में भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। 2019 में फिर मोदी जी की सरकार और 2022 में योगी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया हालाँकि वर्ष 2024 में हमारे प्रयासों के बावजूद परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहल रहे। श्री मौर्य ने कहा कि सपा और कांग्रेस रूपी साँपनाथ और नागनाथ ने झूठ और फरेब कर थोड़े समय के लिए हमें पीछे किया है, लेकिन 2027 में फिर से 300 पार लक्ष्य के साथ प्रदेश में भाजपा सरकार बनायेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता का भाव हनुमानजी जैसा है। वह थोड़े समय के लिए सपा–कांग्रेस के झूठ और फ़रेब के कारण अपनी शक्ति को भूला है। 2027 में वह दोबारा वह अपने सामर्थ्य से विपक्षी गठजोड़ को पराजित करेगा और साबित करेगा कि भाजपा अपराजेय है। स्व. अटल बिहारी बाजपेयी जी के समय हम यह नहीं सोच सकते थे कि केंद्र में भाजपा अकेले के दम पर सरकार बना सकती है। 2014 में कार्यकर्ताओं ने इस मिथक को तोड़ा। 2019 में प्रदेश में सपा–बसपा गठबंधन को पराजित कर मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। उन्होंने कहा कि बहकावे और झूठ का फर्क समझना है। भाजपा विकास के लिए काम करती है। उन्होंने कहा कि झूठ की मशीन बन चुके विपक्ष को जवाब देने का समय आ गया है। वो हमारे मनोबल के आगे नहीं टिक सकते, 2024 में जो कमी रह गई है उसे 2027 में प्रचंड बहुमत की भाजपा सरकार बनाकर अपनी ताकत को साबित कर देंगे। उन्होंने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा था, बड़ा है और हमेशा बड़ा रहेगा। मौर्य ने कहा कि उनके सात कालिदास मार्ग स्थित आवास का दरवाज़ा सबके लिए खुला है। मैं उपमुख्यमंत्री बाद में हूँ पहले कार्यकर्ता हूं। उन्होंने कहा कि जो भी मंत्री हैं, विधायक हैं जनप्रतिनिधि हैं वे सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान दें, उनके मान सम्मान का ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि कार्यसमिति की बैठक में यह तय करके जाना है कि 2027 में सपा बसपा और कांग्रेस एकजुट हो जायें तो भी हमें अपने सामर्थ्य के बल पर 300 पार के लक्ष्य को पार पाना है।

साहब के पंच तीर्थ बनाए गये। संविधान को सिर माथे रखकर नई संसद में स्थापित किया। भाजपा संविधान को सर्वोच्च सम्मान देने वाली पार्टी है। मगर अफवाह और भ्रम फैलाकर माहौल खराब करने का प्रयास किया गया। दुनिया जानती है कि हमारा समाज बिखरा होगा तो आसानी से शिकार हो जाएगा, मगर एकजुट होगा तो बड़ी–बड़ी ताकतें भी इसके सामने धराशाई हो जाएंगी। जाति के नाम पर विभाजित और शक्ति को छिन्न–भिन्न करने का जो पाप इस चुनाव में हुआ है, हमें इससे सतर्क और सावधान होना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना होगा। इसी सोशल मीडिया का उपयोग करके षड्यंत्र के साथ विरोधी ताकतें और विदेशी लगे थे, जिसमें वो सफल हो गये। हम राष्ट्रवादी मिशन वाले लोग हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं को ये देखना होगा कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। हमें अफवाहों का तत्काल खंडन करना होगा। अनुसूचित जाति के महापुरुषों के बारे में भाजपा के विचारों को सबके सामने लाना होगा। 2019 में हमने इसी प्रदेश में सबसे बड़े गठबंधन को धराशाई किया था। 'एक–एक व्यक्ति को जुटना होगा' मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने नगर निकाय चुनाव में सभी 17 मेयर सीटें जीतीं, सर्वाधिक नगर निकायों की सीट हम जीते। प्रदेश में सर्वाधिक चेयरमैन और पार्षद हमारे हैं। आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव में हमने जीत दर्ज की। आने वाले सभी 10 विधानसभाओं के उपचुनाव में भी भाजपा का परचम लहराएगा। इसके लिए हमें अभी से जुट जाना है। यही हमारा संकल्प आज से होना चाहिए। जिले में मेयर से लेकर पार्षद तक हमारा है। एक–एक व्यक्ति को जुटना होगा, ब्लॉक प्रमुख, चेयरमैन, महापौर, जिला पंचायत सदस्य, विधायक, एमएलसी, राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद को मिलकर संकल्प को पूरा करना है। जिन लोगों को आज उछल कूद करने का अवसर मिला है, वो दोबारा उछल कूद नहीं कर पाएंगे।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर नवनिर्वाचित सांसदों को उनके उज्जवल भविष्य और अच्छे कार्यकाल के लिए बधाई और शुभकामनाएं दीं। इससे पहले सुबह के सत्र में उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का स्वागत किया और पौधरोपण भी किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के शुभारंभ से पहले बाबा साहब भीम राव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने पंडित दीन दयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित की।

उत्तर प्रदेश भाजपा की उर्वरा भूमि : ब्रजेश

भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश भाजपा की उर्वरा भूमि है। प्रदेश के असंख्य कार्यकर्ताओं ने अपने खून पसीने से सपा-बसपा और कांग्रेस की अत्याचारी सरकारों से लड़ाई लड़कर भाजपा को सत्ता में लाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से लगातार भाजपा ने यूपी में उत्तरोत्तर प्रगति अर्जित की है। वर्ष 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में 325 सीटें जीतने के अलावा वर्ष 2019 में भी सपा व बसपा का गठबंधन होने के बाद भी भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला। वर्ष 2017 व 2022 में भी कार्यकर्ताओं के परिश्रम व जुझारूपन से दो तिहाई सीटों पर जीत के साथ प्रदेश में भाजपा सरकार बनी।

श्री पाठक ने कहा कि वर्ष 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा जहां पारदर्शिता के साथ काम कर रही थी, वहीं विपक्ष ने भ्रम फैलाया। झूठे वादे किए और हमें आशा के अनुरूप परिणाम नहीं मिले। उन्होंने कहा कि झूठ और फ़रेब की उम्र लंबी नहीं होती। फरेबी विपक्ष के कारनामों के बारे में हमें घर-घर जाकर जानकारी देनी होगी। उन्होंने कहा कि 2027 में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनाने के लिए जीतोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संविधान की धज्जियाँ उड़ाई, इमर्जेंसी लगाकर देश को जेल में तब्दील कर दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी अपमान किया। पाठक ने कहा कि बाबा साहेब के खिलाफ कांग्रेसी इकोसिस्टम काम करता रहा। इसका उल्लेख बाबा साहेब ने अपनी जीवनी में भी किया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल मोदी जी ने ही दलितों और ग़रीबों के लिए काम किया है। चाहे पंचतीर्थों का विकास हो, दलितों को पक्का मकान देना हो या उनके घर के बाहर पक्की सड़क बनानी हो। दलितों और पिछड़ों के कल्याण के लिए योजनाएँ केवल मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने ही किया है। उन्होंने कहा कि आरक्षण को लेकर समाजवादी पार्टी ने हमेशा गुमराह करने का काम किया है। सपा सरकार की नीतियाँ गुंडों, माफियाओं को बढ़ावा देने की रही है। सपा राज में बहू बेटी को अकेले बाहर निकालने नहीं देते थे। व्यापारियों से दिन दहाड़े लूट हो जाती थी। वे डरे और सहमें हुए अपना कारोबार करते थे। बिल्डर भी माफियाओं के चंगुल से निकल नहीं पाये थे। सपा की अराजकता को प्रदेश भूला नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें प्रदेश की आम जनता को, माता-बहनों को, किसानों व कारोबारियों और युवाओं दलितों व पिछड़ों को घर-घर जाकर विपक्ष के कारनामों के बारे में बताना है।

राजनैतिक प्रस्ताव

प्रदेश कार्यसमिति बैठक में राजनैतिक प्रस्ताव प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता ने रखा। जिसका समर्थन श्री संजय राय, श्री सुभाष यदुवंश, श्रीमती प्रियंका सिंह रावत ने किया प्रस्ताव में कहा गया कि उत्तर प्रदेश देश का हृदयस्थल है वह हृदय जहां राम, कृष्ण, बुद्ध बसते हैं, यहाँ विश्व की सबसे प्राचीन नगरी काशी जहां भगवान भूत भावन औघड़ दानी शिव विराजमान होकर पूरे विश्व को अपनी जटाओं में समग्रता से पोशित करते हैं। यहाँ गंगा जमुना सरस्वती का संगम तीर्थराज प्रयाग भी है। यहाँ शक्ति स्वरूपा माँ जगदंबा के विभिन्न शक्ति पीठ है। इस प्रदेश में अध्यात्म भी है, विज्ञान भी है, संस्कृति भी है और समृद्धि भी है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में अपराधी भयक्रान्त है, सेवा व सुशासन का मेल है।

भारत के इतिहास में 6 दशक बाद वर्ष 2024 में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेन्द्र मोदी जी को देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाये जाने का ऐतिहासिक कार्य हुआ है। श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व एवं कुशल मार्गदर्शन में राजग ने अपने राजनैतिक सहयोगियों को साथ लेकर सरकार के लगातार दो सफल कार्यकाल पूर्ण किये हैं, लोकतंत्र के महापर्व के माध्यम से जनता जनार्दन के आशीर्वाद स्वरूप फिर एक बार मोदी सरकार ने अपना तीसरा कार्यकाल प्रारंभ किया है। विकसित भारत के मंत्र के साथ, देश के महान संविधान को नतमस्तक होकर हम पुनः अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ चले हैं। हमे गर्व होता है जब हम देखते हैं कि हमारी कार्यपद्धति से निकला हुआ एक व्यक्तित्व आज देश का नेतृत्व करते हुए पूरे विश्व में भारत की ध्वज पताका फहराने का कार्य कर रहा है। आज माँ भारती अपने सच्चे सपूत के कदमों के माध्यम से विश्वगुरू की उपाधि की ओर शनैः शनैः अग्रसर होती दिख रही है।

विगत दिनों हुए चुनावों में हमें देश भर के अनेक राज्यों में एकतरफा (क्लीन स्वीप) सफलता मिली है जो केन्द्र में हमारी मोदी सरकार बनाने से सहायक सिद्ध हुई है। इसके लिए यह कार्य समिति जनता जनार्दन को धन्यवाद ज्ञापित करती है, साथ ही देशभर के हमारी विचारधारा के सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करती है। यह प्रदेश कार्य समिति श्री नरेन्द्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई भी प्रेशित करती है। हमने देश में फिर एक बार मोदी

सरकार बनाने का संकल्प पूर्ण किया है। किंतु उत्तर प्रदेश में आये चुनाव नतीजे हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहे हैं। निश्चित ही हमें अपने कर्मठ भाजपा कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बाद भी विपक्ष के दिग्भ्रमति करने वाले भ्रामक प्रचार जैसे बाबा साहब डाक्टर भीम राव अंबेडकर जी का **''संविधान परिवर्तन''** हो जाएगा, **''आरक्षण खतरे में हैं''** का भय दिखाकर व प्रत्येक महिला को प्रतिमाह खाते में 8500 का झूठा प्रलोभन देने जैसी अनेकों अफवाहों के कारण हमें आशातीत सफलता नहीं प्राप्त हो पाई। जबकि इतिहास गवाह है कि निजी स्वार्थ में कांग्रेस ने अनेकों बार लोकहित को त्यागकर संविधान में अपनी सुविधानुसार परिवर्तन करने का कार्य किया हे। 25 जून, 1975 को देश में तानाशाह सरकार के द्वारा आपातकाल थोपा गया, जो संविधान पर सीधा हमला था। हमारी सरकार ने 25 जून को संविधान हतया दिवस के रूप में घोशित किया है। हम भारत के संविधान को सिर्फ राजकाज का माध्यम नहीं मानते, बल्कि हमारा संविधान जन–चेतना का हिस्सा हो, इसी ध्येय के साथ हमारी सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू किया हैं। हम ओ0बी0सी0 एवं एस0सी0/एस0टी0 के आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है, हमारी सरकार के द्वारा केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, NEET की सीटों में पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को महत्व दिया गया है। हमने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा भी दिया है।

हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल मार्ग दर्शन में गरीब, युवा, अन्नदाता–किसान, नारी (महिला) के हितों के साथ विकसित भारत बनाने की ओर अग्रसर हुए हैं, विगत वर्षों में राष्ट्र की उपलब्धियों और विकास का आधार गरीब कल्याण एवं सशक्तिकरण रहा है, हमारी सरकार में पहली बार गरीब को ये अहसास हुआ कि सरकार उसकी सेवा में तत्पर हे। कोरोना के कठिन समय में सरकार ने देश को भुखमरी और अराजकता से बचाने के लिए 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने वाली पीएम गरीब कल्याण अन्न वितरण योजना शुरू की। जो अब तक गरीबों को निर्बाध गति से प्राप्त हो रही है। स्वच्छ भारत अभियान ने भी गरीब के जीवन की गरिमा से लेकर उसके स्वास्थ्य तक को राष्ट्रीय महत्व का विषय बनाकर पहली बार देश में 13 करोड़ से ज्यादा गरीबों के लिए इज्जत घर (शौचालय) बनाए। हमारी सरकार 55 करोड़ लोगों को आयुश्मान भारत योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध करवा रही है। अब इस योजना के तहत मुफ्त इलाज का लाभ 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी मिलेगा। देश में सस्ती सुलभ दवाइयों के लिए 25 हजार जनऔषधि केंन्द्रों को खोलने का काम भी तेजी से से कर रही है। पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से 18 प्रकार के लाखों कारीगरों/कर्मकारों व उनके परिवारों को संरक्षित करने का कार्य किया जा रहा है। भाजपा उत्तर प्रदेश कार्य समिति इन सभी प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से अभिनन्दन करती है।

माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प व उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश नित नई ऊंचाई प्राप्त कर रहा है। हम सबका सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी काशी (वाराणसी) का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका आशीर्वाद वा सानिध्य लगातार उत्तर प्रदेश को मिल रहा है। आपने विराट हृदय से गाँव, गरीब, वंचित, महिला, युवा, किसान को संरक्षित व पोषित किया है। हमने प्रदेश में संगठित और सत्ता संरक्षित अपराध को समूल नष्ट किया है, उत्तर प्रदेश को दंगामुक्त प्रदेश बनाया है। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरे देश में उदाहरण बनी हुई है। प्रदेश की लोकप्रिय सरकार बिना सामाजिक भेदभाव के प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए लगी हुई है। हम इस प्रदेश कार्यसमिति की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का आभार प्रकट करते हैं, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश भयमुक्त होकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए विकसित भारत बनाने में अपना योगदान दे रहा है। भाजपा उत्तर प्रदेश की यह कार्यसमिति इस जनादेश को आशीर्वाद स्वरूप लेते हुए गरीब कल्याण को समर्पित रहते हुए उत्तर प्रदेश को विकास पथ पर और भी आगे गति प्रदान करेगी।

संसद की गरिमा

हृदयनारायण दीक्षित

संसद की गरिमा महिमा पर संकट है। संसद राजनैतिक कलह का मंच नहीं है, लेकिन पीछे लंबे समय से संसदीय मर्यादा का जबरदस्त ह्रास हुआ है। अध्यक्ष का आसन सर्वोपरि होता है। संविधान की दुहाई सब देते हैं लेकिन पीठासीन अध्यक्ष/सभापति के निर्देश प्रायः पालन नहीं किए जाते। 18वीं लोकसभा के शपथ ग्रहण के दौरान कुछ सदस्यों ने संवैधानिक शपथ के साथ अपने वाक्य भी जोड़े। यहाँ न मर्यादा बची है और न ही संयम और अनुशासन। संसदीय व्यवस्था में नेता प्रतिपक्ष का पद और दायित्व सम्माननीय है। लेकिन सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गाँधी ने हिन्दुओं को हिंसक कहा। अध्यक्ष ने उन्हें अनुशासित रखने का प्रयास किया। वे नहीं माने। नेता प्रतिपक्ष के वक्तव्य से करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। अध्यक्ष ने आपत्तिजनक अंश कार्यवाही से निकाल दिए हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष सार्वजनिक सभाओं में इसी विवादित वक्तव्य को फिर से जोड़े जाने की मांग कर रहे हैं। वैसे अब कार्यवाही से किसी अंश को निकाले जाने का कोई लाभ नहीं होता। संसद की कार्यवाही का जीवंत प्रसारण होता है। इसलिए सभी मानहानिकारक शब्द बोले जाते समय ही देश की जानकारी में आ जाते हैं।

भारत के लोग संविधान और संसद के प्रति आदरभाव रखते हैं। भारतीय संसद की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा रही है। अनेक सदस्य संसद के लिए पवित्र सदन, आदरणीय सदन या आगस्ट हाउस कहते हैं। संसद जन गण मन की भाग्य विधाता है। राष्ट्र के हर्ष–विषाद, प्रसाद व अभिलाषा का सर्वोच्च जनप्रतिनिधि सदन है। संप्रति संसदीय कार्यवाही में वाक्संयम, प्रेमपूर्ण वाद–विवाद की जगह शोर–शराबा और हुल्लड़ है। प्रतिनिधियों पर विधि निर्माण और संविधान संशोधन की जिम्मेदारी है। आश्चर्य है कि अनेक सदस्य कार्यवाही में बाधा डालते दिखाई पड़ते हैं। सदन की नियमावली की भी उपेक्षा करते हैं। बहुत दिन नहीं बीते जब तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने आहत मन सदन की नियमावली को जला देने की बात कही थी। विधायी संस्थाओं में विधि और नियम का उल्लंघन साधारण घटना नहीं है। सदनों में कार्यवाही की गुणवत्ता की चिंता पुरानी है। ब्रिटिश राज में गठित केन्द्रीय विधानसभा के समय (1921) अध्यक्ष फ्रेडरिक वाइट की अध्यक्षता में पीठासीन अधिकारियों का पहला सम्मेलन शिमला में हुआ था। तब से लगभग हर साल पीठासीन अधिकारियों के अखिल भारतीय सम्मेलन होते हैं। लोकसभा के प्रकाशन 'संसदीय पद्धति और प्रक्रिया' के अनुसार सम्मेलन का उद्देश्य यह देखना रहता है कि शासन की संसदीय प्रणाली का समुचित विकास हो। सदस्यों के संयम और आचरण भी महत्वपूर्ण हैं।

अव्यवस्थित सदनों का भार असहनीय है। संसदीय कार्यवाही निस्तेज हो रही है। राष्ट्र का मन बेचैन है।

संसदीय गतिरोध व अव्यवस्था ने निराश किया है। माननीयों के सम्यक आचरण पर जनता की निगाह रहती है। सांसदों के लिए कोई निश्चित आचार संहिता नहीं है। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन हर साल होते हैं। अनुशासन और शिष्टाचार बनाए रखने का मुद्दा बार–बार चर्चा में आता है। मई 1992 में गुजरात में पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ था। सुझाव आया था कि अनुशासन और शिष्टाचार बनाए रखने पर विचार के लिए अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया जाए। इसके अनुसरण में (23 और 24 सितंबर 1992) संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में पीठासीन अधिकारियों, सदनों के दलीय नेताओं, संसदीय कार्य मंत्रियों और सांसदों आदि की भागीदारी में सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में गंभीर विचार विमर्श हुआ। संसदीय परंपराओं और नियमों के आधार पर आचार संहिता का एक प्रारूप तैयार किया गया और उसे संसद तथा विधानमण्डलों में **'अनुशासन तथा शिष्टाचार'** शीर्षक पत्र में शामिल किया गया। इसे लोकसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित किया गया। सम्मेलन सफल हुआ लेकिन परिणाम नहीं आए।

सम्मेलन में सदस्यों के दायित्व और कर्तव्य के लिए सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया गया। सुझाव दिया गया कि सभी राजनैतिक दल अपने विधायकों के लिए आचार संहिता तैयार करें। अनुपालन सुनिश्चित करें। यह काम राजनैतिक दलों को करना था। दलतंत्र ने उसकी उपेक्षा की। लोकसभा के स्वर्ण जयंती सत्र (26 अगस्त 1997 से 1 सितंबर 1997) में यह विषय फिर विचार विमर्श हेतु आया। सभा ने एकमत से संकल्प पारित किया। संकल्प के अनुसार, ''सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बंधी नियमों, व्यवस्थित कार्य संचालन सम्बंधी पीठासीन अधिकारियों के निर्देशों के गरिमापूर्ण अनुपालन द्वारा संसद की प्रतिष्ठा का परिरक्षण और संवर्धन किया जाए।'' संकल्प खूबसूरत था लेकिन परिणाम शून्य रहा। संकल्प में अन्य बातों के अलावा प्रश्न काल की महत्ता और नारेबाजी पर रोक तथा राष्ट्रपति के अभिभाषण में व्यवधान न करना था। 2001 में नियमों में संशोधन हुआ कि अध्यक्ष के आसन के सामने नारेबाजी करने वाले स्वतः निलम्बित होंगे। निलम्बन भी थोक के भाव हुए, मगर कोई लाभ नहीं हुआ।

13वीं लोकसभा के दौरान अध्यक्ष ने 16 मई 2000 को लोकसभा में 15 सदस्यीय आचार समिति का गठन किया था। समिति को सदस्यों की नैतिकता और आचरण पर ध्यान रखना, सदस्य के संसदीय व्यवहार से सम्बंधित अनैतिक आचरण की शिकायत की जांच करना था। इस समिति ने पहला प्रतिवेदन 31 अगस्त 2001 को अध्यक्ष को प्रस्तुत किया। इसे 22 नवंबर 2001 को सभा पटल पर रखा गया। 16 मई 2002 को सभा ने स्वीकृत कर दिया। व्यवस्था, अनुशासन और संयम और वाक्संयम जैसे सामान्य विषयों पर लगातार बैठकें चलती रहीं। लेकिन ऐसे सम्मेलनों और बैठकों के परिणाम नहीं आए।

सदनों की कार्यवाही का सीधा प्रसारण काफी लोकप्रिय हुआ है। उम्मीद की जाती थी कि सदन के भीतर अपशब्द बोलने, नियम तोड़ने, अध्यक्ष की बात न मानने जैसे व्यवहार को आम जनता देखेगी और अपने जनप्रतिनिधि के अनुचित आचरण का संज्ञान लेगी। यह संभावना गलत निकली। सदनों में हंगामा करने वाले सदस्यों के क्षेत्र में निर्वाचकगण हुल्लड़ देखकर संभवतः दुखी नहीं होते। संभवतः माननीय सदस्य भी नहीं। स्वतंत्रता के बाद 1970 के आसपास तक संसदीय कार्यवाही में लोगों की रुचि थी। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही कार्यवाही की पवित्रता के प्रति सजग थे। विपक्ष में बैठना और तद्नुसार संसदीय कर्तव्य का पालन करना भी महत्वपूर्ण है। शोर–शराबा और हंगामा विपक्ष का काम नहीं है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह के वक्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने लोकसभा के एक प्रकाशन (2011) की भूमिका में लिखा है, ''संसद में अनुशासनहीनता और अव्यवस्था से मर्यादा क्षीण होती है। नागरिकों में लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। आवश्यक है कि संसद लोगों की नजरों में अपनी अधिकाधिक विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए व्यवस्थित ढंग से कार्य करे।''

संसद हुल्लड़ की जगह नहीं है। लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। जनप्रतिनिधि सदनों में अव्यवस्था का लगातार बढ़ना राष्ट्रीय चिंता का विषय है।

संसद हुल्लड़ की जगह नहीं है। लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। जनप्रतिनिधि सदनों में अव्यवस्था का लगातार बढ़ना राष्ट्रीय चिंता का विषय है। बेशक जनप्रतिनिधि जनता से चुने जाते हैं। लेकिन उन्हें सम्बंधित निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए पार्टियां ही उम्मीदवार बनाती हैं।

निर्वाचित प्रतिनिधियों पर दलों का नियंत्रण रहता है। संसदीय समिति ने ठीक ही सिफारिश की थी कि राजनैतिक दल अपने–अपने प्रतिनिधियों के आचरण और व्यवहार पर ध्यान दें। संसद के सभी दलों के संसदीय पदाधिकारी परस्पर संवाद बनाएं। संसद में मर्यादा बनाए रखने के विषय पर संसद का विशेष सत्र आहूत करने पर विचार करें। भारतीय संसद विश्व की सभी जनप्रतिनिधि संस्थाओं से बड़ी है। पवित्र सदन में संवाद के स्थान पर अव्यवस्था उचित नहीं।

कारगिल विजय दिवस की 25 वां वर्षगांठ

कारगिल विजय दिवस

तरुण चुघ

भारतीय इतिहास में कई ऐसी तारीखें हैं, जो भारत के लोगों के मन में हमेशा विद्यमान रहती है। 26 जुलाई की तारीख भी वह ऐतिहासिक तारीख है, जो हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। 26 जुलाई 1999 को वीर भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सेना व सरकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। ये दिन आज भी भारतीय इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इस बार भी भारत देश कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। 26 जुलाई भारतीय सैनिकों का दिन है, क्योंकि यह कारगिल युद्ध के दौरान शहीदों की वीरता को बयां करता है। कारगिल विजय दिवस 1999 के भारत–पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में मनाया जाता है। 1999 में मई और जुलाई के महीनों के बीच लड़ा गया कारगिल युद्ध भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसने भारतीय सशस्त्र बलों के अटूट दृढ़ संकल्प और अदम्य भावना को प्रदर्शित किया।

पूरी दुनिया में भारत को अपने साहस और वीरता के लिए जाना जाता है। लेकिन,भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ता भी किसी से छिपा नहीं है। कारगिल युद्ध वह लड़ाई थी, जिसमें पाकिस्तानी सेना ने द्रास–कारगिल पहाड़ियों पर कब्जा करने की कोशिश की थी। कारगिल युद्ध पाकिस्तान के गलत इरादों का सबूत है। पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख परवेज़ मुशर्रफ ने भारत की सीमाओं में आने की कोशिश की थी। लेकिन, भारत ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और पाकिस्तान को पराजित कर एकबार फिर अपनी ताकत का एहसास दुनिया को करा दिया। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयीजी ने पाकिस्तान को सबक सिखाते हुए भारत के शौर्य और सामर्थ्य का एहसास पूरी दुनिया को कराया। वहीं पाकिस्तान के साथ हमदर्दी दिखानेवाले महाशक्तियों ने जब पाकिस्तान हमले की बात कही तो श्रद्धेय अटल जी ने दो टुक लहजे में ऐसा करार जवाब दिया कि बोलती बंद हो गई थी। उस समय दुनिया ने भारत के आन, बान और शान को देखा। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान की करारी हार के साथ ही उसकी विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचिन्ह खड़ा हो गया। इस युद्ध में भारत ने भी अपने कई वीर योद्धाओं को खोया था और उनका बलिदान इस देश के लिए एक मिसाल बन गया। देश इन सपूतों के बलिदान को कभी नहीं भूले सकेगा। इसलिए हर साल 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस मानते है।

जब से भारत–पाकिस्तान अलग हुए तो तभी से पाकिस्तान की मंशा और हरकत भारत के लिए ठीक नहीं रही। वे कश्मीर पाने के लिए हमेशा घुसपैठ के अलग–अलग तरीके अपनाते रहते है। कारगिल युद्ध का कारण बनने वाले तरीकों में से एक भारत की सीमाओं में प्रवेश करने का प्रयास कुत्सित था। पूर्व की भांति इस बार भी पाकिस्तान विश्वासघात करेगा, इस इरादे से भारत अनजान था। लेकिन इसकी

भनक लगते ही भारत ने तुरंत गश्त कर दी। इस गश्ती टीम पर हमले से उस इलाके में घुसपैठियों की मौजूदगी का प्रमाण मिल गया। पहले तो घुस पैठियों को जिहादी मानकर खदेड़ने के लिए सैनिक भेजे, लेकिन प्रतिद्वंद्वियों के जवाबी हमलों और एक के बाद एक कई इलाकों में घुसपैठियों की मौजूदगी की खबरों के बाद भारतीय सेना को यह समझते देर नहीं लगी कि यह वास्तव में एक योजनाबद्ध और बड़े पैमाने पर घुसपैठ थी, जिसमें न केवल जिहादी बल्कि पाकिस्तानी सेना भी शामिल थी। इसे समझते हुए भारतीय सेना ने **'ऑपरेशन विजय'** शुरू किया, जिसमें 30 हजार भारतीय सैनिक शामिल थे। 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में लगभग पांच सौ से अधिक भारतीय सैनिक मारे गए थे और 1300 सैनिक घायल हुए। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद इस युद्ध को सबसे भयानक माना जाता है। इसके बावजूद सैनिकों ने भारत माता के मस्तक को झुकने नहीं दिया और पाकिस्तानी सैनिकों को रौंदते हुए कारगिल की चोटी पर तिरंगा फहरा दिया था। इस दिन को याद कर आज भी हर भारतीय का सीना गर्व से फूल जाता है। इतने संघर्षो के बाद हमने लड़ाई जीती और अपनी जीत का झंडा फहराया। कारगिल विजय दिवस भारतीय इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इस दिन को हर भारतीय बड़े गर्व के साथ मनाता है। यही वह दिन है जब भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे और घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। भारत–पाकिस्तान का यह युद्ध ऐतिहासिक माना जाता है। अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन विशेष सैनिकों की याद में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में हम भारतवासी हर साल बड़े सम्मान और गर्व के साथ मनाते है। इस ऑपरेशन के नाम के अनुसार 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस घोषित किया गया ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी उन देशभक्तों की वीरतापूर्ण कहानियों के बारे में जानें और उन वीरों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सकें। आज कारगिल और द्रास के क्षेत्र, जिन्हें हम सब गर्व से भारत का अंग बताते हैं, उन शहीदों की देन हैं, जिन्हें हम हर वर्ष विजय दिवस पर श्रद्धांजलि देकर अपना आभार व्यक्त करते है।

भारत में कारगिल युद्ध की जीत का स्मारक बनाया गया है, जहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रति वर्ष इस तारीख को जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते है। युद्ध की जीत की याद में कारगिल विजय दिवस भारत के सभी हिस्सों में मनाया जाता है तथा लोग युद्ध के सैनिकों और शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में अमर जवान ज्योति जाते हैं और वहां सैनिकों को श्रद्धांजलि देते है। स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक समारोह भी आयोजित किये जाते हैं, ताकि उन वीर सपूतों को याद किया जाए। भारत का बच्चा–बच्चा युद्ध और उसके भारत के पक्ष में हुए गौरवशाली परिणाम के बारे में जान सकें। इस दिन पूरा भारत हमारे सैनिकों की वीरता और बलिदान को नमन करता है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सामर्थ्य, सैनिकों का मनोबल भी बढ़ाया। आज हर भारतीय को अपने सैनिकों पर गर्व है। कारगिल विजय दिवस के गौरवमयी दिवस पर हम देश के लिए शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देते है।

(लेखक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं)

विवेकशील और साहसी बजट

डॉ. अरुण कान्त त्रिपाठी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का चिर प्रतीक्षित पहला बजट पूर्व अनुमानों के अनुरूप है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने सातवें बजट में भारत को विकसित देश का दर्जा दिलाने के लिए आवश्यक दीर्घ अवधि के लक्ष्य निर्धारित करने की प्राथमिकता दी है। फरवरी के अंतरिम बजट में व्यक्त अनुमानों की तुलना में भारी भरकम लाभांश मिलने से गैर–कर राजस्व के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है। राजकोषीय घाटे के अनुमान में मामूली सुधार भी किया गया है।

वित्त वर्ष 2024–25 के बजट में तीन जरूरी बातों का समावेश है।

पहला – यह बजट काफी पारदर्शी है और कोई बात या बजट से इतर देनदारी पर्दे के पीछे नहीं है। इसका लाभ है कि भारत के वृहद आर्थिक हालात पर बजट प्रावधानों के असर को समझने में मदद मिल रही है।

दूसरा – कोविड महामारी के बाद राजकोषीय स्थिति सुदृढ़ बनाने के प्रयास तेज किए गए हैं।

तीसरा – मोदी सरकार ने राजकोषीय स्थिति को मजबूत करने के साथ ही पूंजीगत आवंटन भी बढ़ाया है ताकि अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज रहे। जीडीपी के सापेक्ष केंद्र सरकार का पूंजीगत आवंटन निरंतर बढ़ रहा है और यह 2024–25 के बजट में बढ़कर 3.4 प्रतिशत हो गया है, जो 2020–21 में 1.7 प्रतिशत था।

नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्ण बजट में फिर से बताया कि सरकार राजकोषीय विवेक, साहस और राजनीतिक समझदारी सब रखती हैं। वित्तमंत्री का राजकोषीय विवेक न केवल 2024–25 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कम करके सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.9 फीसदी तक लाने का है बल्कि घोषणा में भी दिखता है कि वह राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को 2026–27 से केंद्र सरकार के घाटे में कमी के साथ तालमेल वाला बनाएंगी। 2024–25 के अंतरिम बजट में राजकोषीय घाटे के लिए 5.1 फीसदी का लक्ष्य तय था जिसका मतलब था कि, सरकारी ऋण जीडीपी का 57.2 फीसदी होगा। पेश बजट में घाटे के लिए 4.9 फीसदी का लक्ष्य तय है जो सरकारी ऋण को कम करके जीडीपी के 56.8 फीसदी के स्तर पर लाएगा।

इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए वित्त वर्ष 2025–26 तक राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 4.5 प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया है कि राजकोषीय ढांचा का घाटा धीरे–धीरे कम करने के बाद सरकार इसको और कम करती रहेगी ताकि कर्ज बोझ घटाया जा सके। इसके द्वारा कितनी कमी संभव हो पाएगी और इसमें कितना समय लगेगा इसे लेकर अस्पष्ट है।

कर्ज का स्तर अभी भी आधिकारिक समिति द्वारा कुछ माह पहले तय किए गए 40 फीसदी के लक्ष्य से अधिक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कोविड के बाद के अपने सभी बजट भाषणों में यह लक्ष्य रखा गया कि राजकोषीय घाटे को 2025–26 तक जीडीपी के 4.5 फीसदी तक लाना है लेकिन सरकारी ऋण के स्तर में कमी का जिक्र नही किया गया है।

वित्तमंत्री ने राजकोषीय घाटे को इस गति से कम करने का जिक्र किया जिससे कि सरकारी ऋण के स्तर में भी कमी आए। यह एक स्वागत योग्य और जरूरी बात है जिस पर सरकार की राजकोषीय मजबूती की रणनीति के तहत ध्यान देना आवश्यक था। एक विकासशील अर्थव्यवस्था की अलग तरह की दिक्कतों को देखते हुए कर्ज के स्तर को राजकोषीय मजबूती के अधिक विश्वसनीय आधार के रूप में देखा जा रहा है।

वित्तमंत्री के वित्तीय विवेक को एक और तरह से आंका जा सकता है। उन्होंने रिजर्व बैंक से अतिरिक्त लाभांश मिलने के बावजूद खुद को विभिन्न योजनाओं के लिए अतिरिक्त आवंटन करने से रोके रखा। यह लाभांश जीडीपी के 0.4 फीसदी के बराबर है। उन्होंने इस बात को सही चिह्नित किया कि यह इस वर्ष हुआ लाभ हो सकता है और अगले वर्ष शायद अतिरिक्त लाभांश नहीं हो। ऐसे में इस वर्ष अतिरिक्त धनराशि होने के बावजूद उन्होंने राजस्व आवंटन को छह फीसदी बढ़ने दिया। बिना ब्याज भुगतान के वास्तविक इजाफा 4.78 फीसदी रहा यानी लगभग कोई वृद्धि नहीं हुई। इसके बजाय उन्होंने पूंजीगत व्यय में 17 फीसदी इजाफा बरकरार रखा है। ऐसे में केंद्र सरकार का कुल व्यय 8.5 फीसदी बढ़ने वाला है जबकि उसका कुल राजस्व 15 फीसदी बढ़ेगा।

> **एक विकासशील अर्थव्यवस्था की अलग तरह की दिक्कतों को देखते हुए कर्ज के स्तर को राजकोषीय मजबूती के अधिक विश्वसनीय आधार के रूप में देखा जा रहा है।**

उन्होंने राजस्व घाटे को भी निरंतर कम किया। 2022–23 के जीडीपी के 4 फीसदी के मुकाबले राजस्व घाटा 2023–24 में 2.6 फीसदी रह गया और अब उसके लिए 1.8 फीसदी का लक्ष्य है। राजस्व घाटे में कमी के साथ ही

सरकार के पास यह गुंजाइश होगी कि वह पूंजीगत व्यय में उधारी का अधिक हिस्सा डाले।

वित्त मंत्री इसलिए भी साहसी हैं क्योंकि उन्होंने हर प्रकार की परिसंपत्तियों से हासिल पूंजीगत लाभ पर कर का पुनर्गठन किया है। इसका परिणाम अल्पावधि और दीर्घावधि के पूंजीगत लाभ कर में इजाफे के रूप में सामने आया है। इसके अलावा उन्होंने प्रतिभूतियों के वायदा एवं विकल्प कारोबार पर लगने वाले प्रतिभूति विनिमय कर (एसटीटी) में भी इजाफा किया है। याद रहे कि बजट के पहले आर्थिक समीक्षा में अर्थव्यवस्था के जरूरत से अधिक वित्तीयकरण के जोखिम को रेखांकित किया गया था। शेयर बाजार में वास्तविक अर्थव्यवस्था की तुलना में तेज वृद्धि इसमें शामिल है। समीक्षा में कर नीतियों और पूंजी और श्रम आय के साथ उसके व्यवहार के महत्त्व को भी रेखांकित किया गया है।

बजट में सरकार समर्थित इंटर्नशिप योजना और नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देने की योजना को शामिल कर दें तो हम कह सकते हैं कि 11वें वर्ष में बजट ने एक कड़वे सच से रूबरू कराया है कि भारत की राजनीति में वैचारिक दलीलें चाहे जो हों, समाजवाद राष्ट्रीय द्विपक्षीय आर्थिक विचार है।

ऐसा लगता है कि वित्त मंत्री ने पूंजीगत लाभ कर और एसटीटी को लेकर जो घोषणाएं की हैं वे दरअसल समीक्षा में जताई चिंताओं की बदौलत हैं। परंतु जब बात सालाना बजट की आती है तो शेयर मार्केट के मामले में वित्त मंत्रियों को जोखिम से बचने के लिए जाना जाता है। कुछ ही वित्त मंत्री शेयर बाजार को निराश करने वाली घोषणा करते हैं। सीतारमण ने यह जोखिम उठाने का निर्णय लिया। आश्चर्य नहीं कि घरेलू स्टॉक एक्सचेंज के मानक सूचकांकों में तेजी से गिरावट आई लेकिन बाद में उनमें सुधार देखने को मिला। इसको वित्त मंत्री की राजनीतिक समझदारी माना जायेगा जब उन्होंने रोजगार से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए एक के बाद एक कई घोषणाएं कीं। इनमें केंद्र सरकार की ओर से निजी क्षेत्र को लोगों को काम पर रखने में वित्तीय मदद प्रदान करने की योजना शामिल है। सरकारी नौकरी की बात करने के बजाय उन्होंने निजी क्षेत्र में रोजगार देने के साथ प्रोत्साहन शामिल कर दिए हैं। सूक्ष्म, लघु और मझोले उपक्रमों की बात करें तो उन्होंने संकटग्रस्त इकाइयों के लिए अधिक ऋण और कुछ नियामकीय सहनशीलता दिखाने की घोषणा की।

इससे भी अहम बात है कि उन्होंने बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए योजनाओं और परियोजनाओं की भरमार कर दी। इन दोनों राज्यों में केंद्र सरकार के गठबंधन साझेदारों की सरकार है। उन्होंने ऐसा करते समय ध्यान रखा कि राजकोषीय सेहत पर बुरा असर नहीं पड़े। इन योजनाओं में से कई तो राज्यों के साथ मिली जुली होंगी और आवंटन भी अगले पांच साल के दौरान किया जाएगा।

केंद्र सरकार की पीएम किसान और मनरेगा जैसी योजनओं में आवंटन नहीं बढ़ा है। प्रमुख सब्सिडी पर होने वाले व्यय में 2024–25 में 8 फीसदी की कमी आने की उम्मीद है। ऐसा गेहूं और धान की कम खरीद तथा उर्वरक कीमतों को युक्तिसंगत बनाए जाने के कारण हो रहा है। कुल रक्षा आवंटन में गिरावट है जबकि रक्षा तैयारी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरी ओर, कुछ प्रमुख योजनाएं जिनके आवंटन में अहम इजाफा हुआ है वे हैं ग्रामीण और शहरी आवास योजना, स्वास्थ्य आदि। बजट में सरकार समर्थित इंटर्नशिप योजना और नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देने की योजना को शामिल कर दें तो हम कह सकते हैं कि 11वें वर्ष में बजट ने एक कड़वे सच से रूबरू कराया है कि भारत की राजनीति में वैचारिक दलीलें चाहे जो हों, समाजवाद राष्ट्रीय द्विपक्षीय आर्थिक विचार है। जहां तक बजट के दूरगामी नजरिये की बात है, वित्त मंत्री ने कुछ आश्वस्त करने वाले संदेश दिए हैं। उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक नए आर्थिक नीति ढांचे की बात कही गई है जिसे राज्यों के साथ मिलकर अंतिम रूप दिया जाएगा। आयकर अधिनियम की एक व्यापक समीक्षा होनी है ताकि इसे सरल बनाया जा सके और करदाताओं को निश्चिंतता प्रदान करते हुए विवाद कम किए जा सकें। सीमा शुल्क दरों की नए सिरे से समीक्षा होनी है और यह सब आगामी छह माह में पूरा करना है। वित्त मंत्री ने पहले ही एक दर्जन क्षेत्रों की करीब 50 वस्तुओं की सीमा शुल्क दरों में कमी करके शुरुआत कर दी है। इस भावना को छह महीने में पूरी होने वाली समीक्षा के दौरान बरकरार रखा जाना है तथा उम्मीद है कि इसे अगले बजट में प्रस्तुत किया जाएगा।

पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होने का समय

डॉ. सौरभ मालवीय

पर्यावरण समस्या और समाधान

भारत सहित विश्व के अधिकांश देश पर्यावरण संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ग्रीष्मकाल में भयंकर गर्मी पड़ रही है। प्रत्येक वर्ष निरंतर बढ़ता तापमान पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। देश में गर्मी के कारण प्रत्येक वर्ष हजारों लोग दम तोड़ रहे हैं। यह सब ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है। यह पृथ्वी की सतह का दीर्घकालिक ताप है, जो मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न हुआ है। विगत कुछ दशकों में जिस तीव्र गति से जलवायु परिवर्तन हो रहा है वह चिंता का विषय है। इसके भयंकर दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। कहीं सूखा पड़ रहा है तथा भूजल स्तर बहुत नीचे चला गया है। लोग पेयजल के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली के निवासी भी जल संकट से जूझ रहे हैं। कहीं अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दिल्ली के अनेक क्षेत्र भी बाढ़ की चपेट में आते रहते हैं। देश की राजधानी की इस स्थिति से पता चलता है कि समस्या कितनी गंभीर है। इससे देश के अन्य क्षेत्रों की स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वायु प्रदूषण भी मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो रहा है।

स्वार्थ से बढ़ा संकट

मानव अपने स्वार्थ के लिए निरंतर प्रकृति को हानि पहुंचा रहा है। वनों से वृक्ष काटकर उन्हें समाप्त किया जा रहा है। विकास के नाम पर भी वृक्ष काटे जा रहे हैं। पर्वतों में खनन किया जा रहा है। मानव ने वन समाप्त करके वन्य प्राणियों के लिए आश्रय एवं भोजन का संकट उत्पन्न कर दिया है। कृषि भूमि पर कॉलोनियां बसाई जा रही हैं। इससे कृषि भूमि कम हो रही है। अत्यधिक रसायनों एवं कीटनाशकों के प्रयोग से उपजाऊ भूमि बंजर होती जा रही है। इससे निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्न का संकट उत्पन्न हो सकता है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक जल स्रोत तालाब, जोहड़ व अन्य जलाशय समाप्त हो रहे हैं। नदियां अत्यधिक दूषित एवं विषैली हो रही हैं। इससे जलीय जीवों के लिए संकट उत्पन्न हो गया है। प्लास्टिक कचरे से भी प्रदूषण बढ़ रहा है। इसलिए समस्त जीवों को बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण अत्यंत आवश्यक है।

पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता

पर्यावरण शब्द संस्कृत भाषा के 'परि' एवं 'आवरण' से

मिलकर बना है अर्थात जो चारों ओर से घेरे हुए है वही पर्यावरण है। जिस पर्यावरण में हम रहते हैं, हमें उसे संरक्षित करना होगा अर्थात हमें अपने चारों ओर के वातावरण को संरक्षित करना होगा तथा इसे जीवन के अनुकूल बनाना होगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए जल संरक्षण, मृदा संरक्षण, वन संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण तथा जैव विविधता संरक्षण पर गंभीरता से कार्य करना होगा।
यह सर्वविदित है कि मानव शरीर पंचमहाभूत से निर्मित है, जिनमें आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी सम्मिलित है। प्राणियों के लिए वायु एवं जल अत्यंत आवश्यक है। उन्हें जीवित रहने के लिए भोजन भी चाहिए, जो भूमि से प्राप्त होता है। वनों से हमें जीवनदायिनी औषधियां प्राप्त होती हैं। इसलिए हमें वायु, जल, वन एवं मृदा को संरक्षित करना होगा।

हानिकारक औद्योगिक कचरे को समाप्त करके भी भूमि को दूषित एवं ऊसर होने से बचाया जा सकता है। प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर कपड़े के थैलों का उपयोग करके प्लास्टिक कचरे को कम किया जा सकता है।
वनों का संरक्षण करके भी पर्यावरण को स्वच्छ बनाया जा सकता है। वन संरक्षण का उद्देश्य यह कि वनों को कटने से बचाया जाए तथा अधिक से अधिक पौधारोपण किया जाए। यदि कहीं विकास कार्यों के कारण वृक्ष काटने अति आवश्यक हों, तो उनसे अधिक संख्या में पौधारोपण किया जाए, जिससे उनकी कमी को पूर्ण किया जा सके। वन विभिन्न प्राणियों के आश्रय स्थल हैं। इन्हें सुरक्षित रखकर वन्य जीवों के आश्रय स्थल की भी रक्षा की जा सकती है।
पर्यावरण संरक्षण के लिए देश में कई अधिनियम हैं। इनमें भारतीय वन अधिनियम–1927, वन्य जीवन संरक्षण

जल संरक्षण के लिए प्राकृतिक रूप से बने जलाशयों को संरक्षित करना होगा। नए तालाब बनाने होंगे। जल संग्रहण करना होगा अर्थात वर्षा के जल को विभिन्न विधियों से संचित करना होगा। तालाब एवं जोहड़ों के अतिरिक्त भूमि के नीचे बनाए गए टैंक के माध्यम से भी वर्षा जल संचयित किया जा सकता है। इसके साथ–साथ जल को व्यर्थ बहने से रोकना होगा। जितनी आवश्यकता हो, उतने ही जल का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त नदियों एवं अन्य जलाशयों को प्रदूषित होने से भी बचाना होगा।
मृदा का संरक्षण भी अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए रिक्त पड़ी भूमि पर पौधारोपण किया जा सकता है। इससे एक ओर हरियाली में वृद्धि होगी, तो दूसरी ओर मृदा कटाव रुकेगा तथा भूमि ऊसर होने से भी बचेगी। इसके अतिरिक्त

अधिनियम– 1972, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम– 1974 तथा 1977, वन संरक्षण अधिनियम– 1980, वायु (प्रदूषण एवं नियंत्रण) अधिनियम– 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम–1986, जैव–विविधता संरक्षण अधिनियम– 2002, राष्ट्रीय जलनीति– 2002, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति– 2004 एवं वन अधिकार अधिनियम– 2006 प्रमुख रूप से सम्मिलित हैं।
सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए कई योजनाएं चला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2021 में घोषित पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अभियान को आगे बढ़ाने के लिए, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दो अग्रणी पहल की हैं। प्रथम ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है, जो पर्यावरणीय गतिविधियों को प्रोत्साहन प्रदान करता है। विगत 13 अक्टूबर, 2023 को अधिसूचित ग्रीन क्रेडिट

प्रोग्राम एक अभिनव बाजार–आधारित व्यवस्था है जिसे व्यक्तियों, समुदायों, निजी क्षेत्र के उद्योगों और कंपनियों जैसे विभिन्न हितधारकों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका शासन ढांचा एक अंतर–मंत्रालयी संचालन समिति द्वारा समर्थित है तथा भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के प्रशासक के रूप में कार्य करता है। यह कार्यक्रम कार्यान्वयन, प्रबंधन, निगरानी और संचालन के लिए उत्तरदायी है। यह प्रोग्राम अपने प्रारंभिक चरण में दो प्रमुख गतिविधियों जल संरक्षण और वनीकरण पर ध्यान केंद्रित करता है। ग्रीन क्रेडिट देने के लिए प्रारूप पद्धति विकसित की गई है और हितधारक परामर्श के लिए इसे अधिसूचित किया जाएगा। ये पद्धतियां प्रत्येक गतिविधि अथवा प्रक्रिया के लिए मानक निर्धारित करती हैं, जिससे सभी क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रभाव और प्रतिस्थापना सुनिश्चित की जा सके। एक उपयोगकर्ता– अनुकूल डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म परियोजनाओं के पंजीकरण, उसके सत्यापन और ग्रीन क्रेडिट जारी करने की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करेगा। विशेषज्ञों के साथ भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद द्वारा विकसित किया जा रहा ग्रीन क्रेडिट रजिस्ट्री और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, पंजीकरण और उसके बाद ग्रीन क्रेडिट के क्रय एवं विक्रय की सुविधा प्रदान करेगा।

द्वितीय ईकोमार्क योजना है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण–अनुकूल उत्पादों को प्रोत्साहन प्रदान करना है। पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली के पीछे का दर्शन व्यक्तिगत विकल्पों और व्यवहार को स्थिरता की ओर ले जाना है। इस दृष्टिकोण के अनुरूप, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपनी ईकोमार्क अधिसूचना को फिर से तैयार किया है, ताकि उपभोक्ता उत्पादों के बीच चयन करने में सक्षम हो सकें और इस तरह उन उत्पादों को चुन सकें जो उनके डिजाइन, प्रक्रिया आदि में पर्यावरण के अनुकूल हैं। जो जलवायु परिवर्तन, स्थिरता और पर्यावरण के प्रति जागरूक प्रथाओं को प्रोत्साहन देने के लिए देश के सक्रिय दृष्टिकोण का संकेत देती हैं। ये योजनाएं परंपरा एवं संरक्षण में उपस्थित पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को प्रोत्साहित करती हैं, जो पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली की अवधारणा के विचारों को प्रदर्शित करती हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं– "हमारे लिए पर्यावरण की रक्षा आस्था का विषय है। हमारे पास प्राकृतिक संसाधन हैं क्योंकि हमारी पिछली पीढ़ियों ने इन संसाधनों की रक्षा की। हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ऐसा ही करना चाहिए।" प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी प्रयासों से भारत पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन की दिशा में ठोस पहल करने वाला अग्रणी देश बना है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों को दर्शाने वाली एक घटना का उल्लेख करते हुए कहा था कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब गुजरात 'जलवायु परिवर्तन विभाग' वाला देश का प्रथम राज्य बना था। यह एक अनूठा प्रयास था, जबकि तब केंद्रीय स्तर पर पर्यावरण मंत्रालय ने भी जलवायु परिवर्तन की अवधारणा को एकीकृत नहीं किया था।

लोकसभा चुनाव के भारतीय जनता पार्टी के 'भाजपा का संकल्प मोदी की गारंटी 2024' नामक घोषणा पत्र में पर्यावरण का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई पर्यावरण के लिए जीवन शैली की अवधारणा को विश्व ने स्वीकार किया है। इस मंत्र को साकार करने के लिए हमने पर्यावरण प्रबंधन के सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया है। हम पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली में विश्व का नेतृत्व करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम पारंपरिक ज्ञान के साथ–साथ आधुनिक प्रथाओं का उपयोग करके एक स्वस्थ समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध हों। हमने कई ऐसी योजनाएं क्रियान्वित की हैं, जिससे पर्यावरण की सुरक्षा होगी। जैसे प्रधानमंत्री सूर्य का घर योजना, रेलवे का विद्युतीकरण, ई–बस, इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रसार एथेनॉल और बॉयो फ्यूल का उपयोग इत्यादि। इन सब योजनाओं से हम नेट जीरो के लक्ष्य की प्राप्ति की ओर तीव्र गति से अग्रसर हैं तथा इन योजनाओं से हमारे नागरिकों के लिए वातावरण सुनिश्चित होगा।

विगत विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पौधा लगाकर 'एक पौधा मां के नाम' नामक अभियान प्रारंभ किया। उन्होंने एक्स पर लिखा था– 'मैंने प्रकृति मां की रक्षा करने और सतत जीवन शैली अपनाने की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप एक पेड़ लगाया। मैं आप सभी से यह आग्रह करता हूं कि आप भी हमारे ग्रह को बेहतर बनाने में योगदान दें।'

इसमें दो मत नहीं है कि सरकारी प्रयास एवं जनभागीदारी से पर्यावरण को संरक्षण किया जा सकता है। हमें अपने बच्चों को भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण मिल सके।

(लेखक–लखनऊ विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर है)

नए आपराधिक कानूनों पर एक दृष्टि

डॉ. चेत नारायण सिंह

भारतीय संसद ने तीन ऐतिहासिक कानूनों –भारतीय दंड संहिता, 1860, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को क्रमशः भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 से प्रतिस्थापित करके आपराधिक न्याय प्रणाली में एक परिवर्तनकारी कदम उठाया है। भारतीय मूल्यों पर आधारित ये नए कानून दंडात्मक से न्याय–उन्मुख दृष्टिकोण में बदलाव का संकेत देते हैं, जो 'भारतीय न्याय व्यवस्था' को प्रतिबिंबित करता है।

औपनिवेशिक युग के कानून ब्रिटिश हितों की रक्षा के लिए बनाये गये थे। इनमें भारतीयों से परामर्श नहीं किया गया था तथा इनमें ब्रिटिश केंद्रित शब्दावली और रूपरेखाएं अंतर्निहित थीं।

ये विधायी परिवर्तन 'आजादी का अमृत महोत्सव' की परिणति को चिह्नित करते हैं और 'अमृत काल' की शुरूआत करते हैं जो वास्तव में स्वतंत्र भारत के निर्माण का प्रतीक है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व एवं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के दिशा–निर्देश में संशोधन प्रक्रिया वर्ष 2019 में प्रारंभ हुई, जिसमें विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श शामिल था और न्यायपालिका के सदस्य, कानून विश्वविद्यालय, राज्य के अधिकारी और आम नागरिक शामिल थे। यह सहयोगात्मक प्रयास सुनिश्चित करता है कि नए कानून ऐसी न्याय प्रणाली है जो पूरी तरह से स्वदेशी होगी, यह भारत द्वारा, भारत के लिए और भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार संचालित होगी।

इसका मुख्य लक्ष्य ऐसी आपराधिक न्याय प्रणाली बनाना है जो न केवल नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है, बल्कि कानूनी व्यवस्था को भी और अधिक मजबूत बनाती है जिससे सभी के लिए सुलभ एवं त्वरित न्याय सुनिश्चित हो। यह सुधार भारत में एक निष्पक्ष, आधुनिक और न्यायपूर्ण कानूनी ढांचे की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

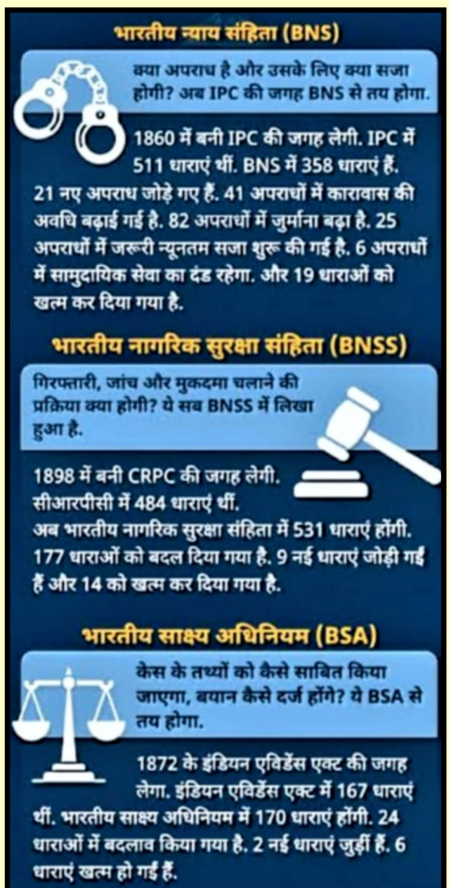

इन कानूनों का उद्देश्य भारतीय कानूनी प्रणाली में सुधार करना और भारतीय सोच पर आधारित न्याय प्रणाली स्थापित करना है।

- ❋ नए आपराधिक कानून 'लोगों को औपनिवेशिक मानसिकता और उसके प्रतीकों से मुक्त करेंगे' और हमारे मन को भी उपनिवेशवाद से मुक्त करेंगे।
- ❋ यह 'दंड के बजाय न्याय पर ध्यान केन्द्रित' है।
- ❋ 'सबके साथ समान व्यवहार' मुख्य विषय है।
- ❋ यह कानून भारतीय न्याय संहिता की वास्तविक भावना को प्रकट करते हैं।
- ❋ इन्हें भारतीय संविधान की मूल भावना के साथ बनाया गया है।
- ❋ यह कानून व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं।
- ❋ यह मानव अधिकारों के मूल्यों के अनुरुप है।यह पीड़ित –केन्द्रित न्याय सुनिश्चित करेंगे।
- ❋ इन कानूनों की आत्मा न्याय, समानता और निष्पक्षता है।

भारतीय लोकाचार को अपने मूल में रखने वाले नए आपराधिक कानून अधिक नागरिक केन्द्रित बनने की दिशा में बदलाव के प्रतीक हैं।

बीएनएसएस की धारा 173 (1) में नागरिकों को मौखिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक संचार (ई–एफआईआर), बिना उस क्षेत्र पर विचार किए जहां अपराध किया गया है, एफआईआर दर्ज करने का अधिकार दिया गया है।

'बीएनएसएस की धारा 173 (2) (1) के तहत नागरिक बिना किसी देरी के पुलिस द्वारा अपनी एफआईआर की एक नि शुल्क प्रति प्राप्त करने के हकदार है।

'बीएनएसएस की धारा 193 (3) (पप) के तहत पुलिस को 90 दिनों के भीतर जांच की प्रगति के बारे में पीड़ित को सूचित करना अनिवार्य है।

'बीएनएसएस की धारा 184 (1) के अनुसार पीड़िता की मेडिकल जांच उसकी सहमति से और अपराध की सूचना मिलने के 24 घंटे के भीतर की जाएगी। बीएनएसएस की चारा 184 (6) के तहत मेडिकल रिपोर्ट चिकित्सक द्वारा 7 दिनों के भीतर भेजी जाएगी।

बीएनएसएस धारा 18 (8) के तहत नागरिकों को अभियोजन पक्ष की सहायता के लिए अपना स्वयं का कानूनी प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है।

- ✶ आपराधिक न्याय प्रणाली को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और सुलभ बनाया गया है। धारा 230 बीएनएसएस में नागरिकों को दस्तावेज उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।
- ✶ बीएनएसएस की धारा 396, इसमें पीड़ित नागरिकों को मुफ्त चिकित्सा उपचार और मुआवजे का अधिकार है।
- ✶ बीएनएसएस की धारा 398 के अंतर्गत गवाह संरक्षण योजना का प्रावधान किया गया है।
- ✶ धारा 360 बीएनएसएस में अभियोजन से हटने के लिए सहमति देने से पहले न्यायालयों को पीड़ित की बात सुनने का अधिकार दिया गया है। यह आपराधिक न्याय के लिए **'न्याय केन्द्रित दृष्टिकोण'** का सबसे अच्छा उदाहरण है।

बीएनएसएस की धारा 404 के तहत पीड़ितों को न्यायालय में आवेदन करने पर निर्णय की निःशुल्क प्रति प्राप्त करने का अधिकार मिला है।

धारा 530 बीएनएसएस कानूनी जांच, पूछताछ और मुकदमे की कार्यवाही को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयोजित करने का प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS)

मुख्य परिवर्तन

- ✶ आईपीसी में धाराओं की संख्या 511 से घटाकर बीएनएस में 358 कर दी गई
- ✶ 20 नये अपराध जोड़े गए
- ✶ कई अपराधों के लिए अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान किया गया है।
- ✶ 6 छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है।
- ✶ कई अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया है।
- ✶ 'कई अपराधों में सजा की अवधि बढ़ाई गई है।

कुछ विशेषताएं

- ✶ महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को एक अध्याय में समेकित किया गया है।
- ✶ धारा 69% झूठे वादे पर यौन संबंध बनाने पर सख्त सजा का प्रावधान किया गया है।
- ✶ धारा 70 (2)% सामूहिक बलात्कार की सजा में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है।
- ✶ :भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS)।

मुख्य परिवर्तन

- ✶ सीआरपीसी में धाराओं की संख्या 484 से बढ़ाकर बीएनएसएस में 531 की गई।
- ✶ 177 धाराओं को प्रतिस्थापित किया गया।
- ✶ 9 नई धाराएं जोड़ी गई।

★ 14 धाराएं निरस्त की गई।

कुछ विशेषताएं

★ जांच में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा।

★ मजिस्ट्रेट द्वारा जुर्मानों में वृद्धि की गई है।

★ FIR प्रक्रियाओं और पीड़ितों की सुरक्षा को सुव्यवस्थित करना।

★ धारा 173% जीरो FIR और e-FIR का प्रावधान किया गया है।

★ 'धारा 176 (1) (ख)% यह कानून ऑडियो–वीडियो के माध्यम से पीड़ित को बयान रिकॉर्डिंग का अधिकार देता है

★ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA)

बदल गई आईपीसी की इन धाराओं की पहचान

जुर्म	आईपीसी	भारतीय न्याय संहिता
देशद्रोह	धारा 124	धारा 152
गैर-कानूनी सभा	धारा 144	धारा 189
हत्या	धारा 302	धारा 101
हत्या का प्रयास	धारा 307	धारा 109
दुष्कर्म	धारा 376	धारा 63
मानहानि	धारा 399	धारा 356
ठगी	धारा 420	धारा 316

मुख्य परिवर्तन

★ आईईए में धाराओं की संख्या 167 से बढ़ाकर बीएसए 170 की गई।

★ 24 धाराएं बदली गई।

★ 2 नई धाराएं जोड़ी गई।

★ 6 धाराएं निरस्त की गई।

कुछ विशेषताएं

★ इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में मान्यता देता है।

★ डिजिटल साक्ष्य प्रामाणिकता के लिए रूपरेखा प्रदान करता है।

★ धारा 2 (1) (घ)% दस्तावेजों की विस्तारित परिभाषा।

★ धारा 61% डिजिटल रिकॉर्ड की स्वीकार्यता में समानता दी गई है।

★ धारा 62 और 63% इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता दी गई है।

★ नए आपराधिक कानूनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए 37 धाराएं शामिल हैं।

★ महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को पीड़ित और अपराधी दोनों के संदर्भ में लिंग तटस्थ बनाया गया है। (धारा 2 बीएनएसएस)

★ 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। (धारा 70 बीएनएस)

★ झूठे वादे या छद्म पहचान के आधार पर यौन शोषण करना अब आपराधिक कृत्य माना जाएगा। (धारा 69 बीएनएस)

★ चिकित्सकों को बलात्कार से पीड़ित महिला की मेडिकल रिपोर्ट सात दिनों के भीतर जांच अधिकारी को भेजने का आदेश दिया गया है। (धारा 51 (3) बीएनएसएस)

★ आपराधिक न्याय प्रणाली के सभी चरणों का व्यापक डिजिटलीकरण किया गया। इसमें ई–रिकॉर्ड, जीरो–FIR, e-FIR, समन, नोटिस, दस्तावेज प्रस्तुत करना और ट्रायल शामिल हैं। (धारा 173 बीएनएसएस)

'पीड़ितों के इलेक्ट्रॉनिक बयान के लिए ई–बयान तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गवाहों, अभियुक्तों, विशेषज्ञों और पीड़ितों की उपस्थिति के लिए e-Appearance की शुरूआत की गई। (धारा 530 बीएनएसएस)

'दस्तावेजों की परिभाषादि सर्वर लॉग, स्थान संबंधी साक्ष्य और डिजिटल वॉयस संदेश शामिल होंगे।

साक्ष्य का कानून अब इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को अदालतों में भौतिक साक्ष्य के बराबर मानता है। (धारा 2 (1) (क) बीएसए) 'कानून के तहत द्वितीयक साक्ष्य का दायरा व्यापक हो गया है जिसमें मौखिक स्वीकारोक्ति, लिखित स्वीकारोक्ति और दस्तावेज की जांच करने वाले कुशल व्यक्ति का साक्ष्य शामिल है। (चारा 58 बीएसए)

'तलाशी और जब्ती की वीडियोग्राफी के लिए प्रक्रियाएं शुरू की गई, जिसमें जब्त वस्तुओं की सूची और गवाहों के हस्ताक्षर तैयार करना शामिल है। (धारा 105 बीएनएसएस)

विकसित भारत का अर्थसंकल्प

डॉ. हरनाम सिंह

विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए यह रणनीतिक बजट है। ग्रीन इकोनॉमी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, कृषि और किसानों के कल्याण, छोटे कारोबारीयों, स्टार्टअप और इनोवेशन इकोसिस्टम,कौशल विकास, मानव संसाधन और सामाजिक न्यायबढ़ाने पर फोकस है। यह बजट युवाओं के लिए नए अवसर प्रदान करनेका ब्ल्यू प्रिंट है।कृषि और किसानों के कल्याण की प्रतिबद्धता और अनुकूल औद्योगिक वातावरण निर्माण कर सशक्त –समर्थ– समृद्ध और संभावनाओं वाले भारत को विकसित भारत तरफ अग्रसर करेगा । यह बजट राष्ट्र सर्वोपरि की धारणा को मजबूत करने के साथ ही देश के उन क्षेत्रों पर और अधिक ध्यान देने का भरोसा दिलाता है जो प्रगति में पीछे रहे हैं ।बिना गारंटी मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लख रुपए करने पर छोटे कारोबारी, महिलाओंऔर वंचितों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। बजट छोटे व्यापारियों वह एमएसएमई के लिए प्रगति का नया मार्ग भी प्रशस्त करेगा ।बजट में मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया गया है इससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड लोग गरीबी से बाहर निकले हैं और इनका एक नया मध्यम वर्ग बना है यह उनके सशक्तीकरण का भी बजट है।शिक्षा एवं कौशल विकास को भी एक नया आयाम प्रदान करेगा। खाद्यान्न भंडारण और सब्जी उत्पादन क्लस्टर शुरू करने की योजना हैं जिनसे किसान और मध्यम वर्ग को मदद मिलेगी। कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए दालों एवं तिलहन का उत्पादन बढ़ाने में किसानों की मदद करने के लिए उपाय की घोषणा की गई है। पूर्वोदय विजन से देश के पूर्वी क्षेत्र के विकास को नई गति और ऊर्जा मिलेगी। गरीबों के लिए घरों और जनजाति उन्नत ग्राम अभियान पर फोकस है। बजट स्टार्टअप और इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए एन्जल टैक्स समाप्त कर नई अवसर प्रदान कर रहा है। एंजल टैक्स खत्म करने से यह बजट नए उद्यमियों को समृद्धि की राह पर ले जाएगा। भारत के पास युवा आबादी और सबसे तेजी से बढ़ाने वाली अर्थव्यवस्था है। ऐसे सभी संसाधन है जिनकी मदद से हम 2047तक विकसित देश बन सकते हैं। केंद्र सरकार ने बजट में ऐसे नौ क्षेत्रों की पहचान की है जो आने वाले समय में भारत को विकासशील से विकसित देश की कतार में खड़ा करेंगे। सरकार ने 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए जिन नौ क्षेत्रों को प्राथमिकता में लिया है वह है– कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास व सामाजिक न्याय, विनिर्माण व सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना, नवाचार, अनुसंधान व विकास और अगली पीढ़ी के सुधार।

नई कर प्रणाली में बदलाव से परिवारों की बचत बढ़ेगी जिससे मांग एवं खपत में वृद्धि की उम्मीद जगी है ।

नई कर व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़कर मध्यम वर्ग की सुध सरकार ने ली है। नई कर व्यवस्थाएं करदाताओं के लिए कुल आय पर स्टैंडर्ड डिडक्शन को ₹50000 से बढ़कर 75000 कर दिया है। अब 7.75 लाख तक आय पर कर नहीं लगेगा। एंजल टैक्स खत्म होने से बढ़ेंगे स्टार्टअप एमएसएमई के लिए सरकार की ऋण गारंटीविशेष किस्म के विकास के लिए व्यापक अनुसंधान के जरिए खेती किसानी की कायाकल्प की योजना बनाई है। करीब 109 उच्च उत्पादक वाली किस्मसे न केवल खाद्य सुरक्षा के लिए कवच की भूमिका निभाएंगे बल्कि इसे किसने की आय भी सुधरेगा। प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा और बायो इनपुट संसाधन केन्द्रों की स्थापना से कृषि को बड़ा संबल मिलेगा ।बड़े वेजिटेबल क्लस्टर और कृषि में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की पहल से आपूर्ति सुधारने के साथ ही बाजारों तक किसानों की पहुंच आसान होगी। कौशल विकास एवं रोजगार के लिए विशेष पैकेज में 2 लाख करोड रुपए का प्रावधान है। जिससे 4.1 करोड़ युवा लाभान्वित होंगे। पहली बार नौकरी में आए कर्मियों को ₹15000 तक का एक महीने का पारिश्रमिक दिया जाएगा जिससे 2.1 करोड़ युवाओं को लाभ मिलेगा। विनिर्माण में रोजगार सृजन को प्रोत्साहन से 30 लाख नए कर्मियों को फायदा पहुंचेगा। अतिरिक्त कर्मियों की भर्ती पर नियुक्ताओं को ₹3000 प्रतिमा दिए जाएंगे जिसके माध्यम से 50 लाख नई भर्तियों की योजना है । महिलाओं को रोजगार में भागीदारी बढ़ाने के लिए कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल से लेकर अन्य सुविधाएं विकसित की जाएगी। कौशल विकास के लिए 1000 आईटीआई को उन्नत करना, 20 लाख युवाओं का केंद्रीय योजनाओं के जरिए कौशल विकास और आदर्श कौशल ऋण योजना को नए सिरे से तैयार किया गया है। पीएम विश्वकर्मा, पीएम स्वनिधि और राष्ट्रीय आजीविका मिशन के जरिए दस्तकारों, स्वयं सहायता समूह और स्ट्रीट वेंडर्स को मदद दी जाएगी। पूर्वोत्तर पूर्वोदय योजना के तहत बिहार, झारखंड. बंगाल, उड़ीसा और आंध्र में इंफ्रास्ट्रक्चर एवं मानव संसाधन विकास के जरिए वृद्धि को नए पंख लगाए जाएंगे। एमएसएमई के लिए नई क्रेडिट गारंटी स्कीम, मशीनरी एवं उपकरण खरीदारी में मददगार होगी। ईजी आफ डूइंग बिजनेस, डाटा गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी एडॉप्शन में भी आर्थिक सक्षमता बढ़ाने भरपूर अवसर हैं। विकसित भारत की तरफ अग्रसर से साफ है कि कृषि उत्थान के साथ–साथ रोजगार के आधिकाधिक अवसर पैदा करना सरकार के प्राथमिकता है। बजट का जोर कृषि के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, कृषि में तकनीक को बढ़ावा देने और किसानों का रुझान प्राकृतिक खेती की ओर करने पर है। बजट में रोजगार की सवाल का समाधान करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। सरकार 500 बड़ी कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराएगी और उन्हें ₹5000 महीना देगी । इस दायरे में अन्य कंपनियां भी लाई जाए ताकि अत्यधिक युवाओं का कौशल विकास हो सके ।बजट देश को विकसित बनाने में सहायक बनने वाली योजनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित रखकर वित्तीय अनुशासन की प्राथमिकता दी है। कुल मिलाकर कौशल विकास एवं रोजगार में लक्षित निवेश के माध्यम से बजट में सतत एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि के मध्यम से विकसित भारत का खाका खींचा गया है।विकसित भारत का लक्ष्य केंद्र और राज्य के सहयोग से ही हासिल किया जा सकता है।

स्व0 प्रभात झां पंचतत्व में विलिन

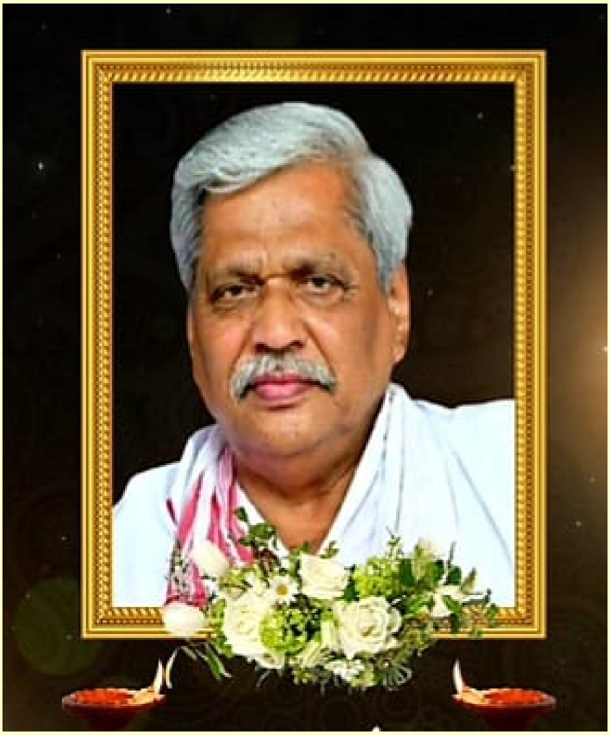

भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मध्यप्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा का निधन हो गया है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। 67 वर्षीय झा लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके बेटे अयत्न ने कहा कि अंतिम संस्कार बिहार के सीतामढ़ी जिले के कोरियाही गांव में होगा।

प्रभात झा मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे। उनका जन्म 4 जून 1957 को बिहार के दरभंगा के हरिहरपुर गांव में हुआ था। वे परिवार के साथ मध्यप्रदेश के ग्वालियर आ गए थे। प्रारंभिक शिक्षा के बाद प्रभात झा ने ग्वालियर के पीजीवी कॉलेज से बीएससी, माधव कॉलेज से राजनीति शास्त्र में एमए और एमएलबी कॉलेज से एलएलबी की डिग्री ली।

उनकी शादी रंजना झा से हुई थी। दो बेटे हैं। बड़े बेटे तुष्मुल और छोटे अयत्न झा हैं।

शादी के बाद वे पत्रकारिता करने लगे। दिल्ली से प्रकाशित कमल संदेश के वे सम्पादक रहे। उ0प्र0 से भी उनका गहरा सम्बन्ध रहा। पूर्व के चुनावों में उत्तर प्रदेश में मीडिया प्रबन्धन निमित्त आपका प्रवास होता रहा है।

उनके निधन से पार्टी को अपूर्णनीय क्षति हुई है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। कमल ज्योति परिवार ने उनके निधन को भाजपा सहित पत्रकारिता जगत की क्षति बताया एवं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिवार को इस दुःख को सहन करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया।

भारतीय जनता युवा मोर्चा
25th ANNIVERSARY OF
KARGIL VIJAY

कारगिल विजय दिवस
के अवसर पर
मुख्य अतिथि

vivo

पत्रिका पंजीकरण – RNI-51899/91, शीर्षक कोडः UPHIN16701, डाक पंजीकरण – SSP/LW/NP-117-2024-26
जुलाई द्वितीय अंक 2024 – प्रेषित डाकघर – R.M.S. चारबाग, लखनऊ – प्रेषण तिथि : 26–28 (द्वितीय पाक्षिक)

भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्रक तथा प्रकाशक प्रो. श्यामनन्दन सिंह द्वारा नूतन ऑफसेट मुद्रण केन्द्र, संस्कृति भवन, राजेन्द्र नगर, लखनऊ से मुद्रित व भाजपा कार्यालय, 7, विधानसभा मार्ग, लखनऊ से प्रकाशित।